● वर्ष-4
● अंक-24
रायपुर, गुरुवार
05 सितंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› फोटोग्राफी की इन शाखाओं में...

हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से सीमाओं को लेकर वार्ता करेगा भारत

बैठक के लिए तारीखों का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच अगले महीने पारंपरिक द्विवार्षिक सीमा वार्ता होने की उम्मीद है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा वार्ता की तारीखों का प्रस्ताव रखा है, वहीं सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश का एक उच्च-स्तरीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडल अगले महीने भारत आ सकता है। पिछले महीने शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सूचनाओं के आदान-प्रदान और साझा करने के लिए दोनों पड़ोसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की ये पहली बैठक होगी।

डीजी के नेतृत्व में वार्ता- जानकारी के मुताबिक बीएसएफ महानिदेशक (डीजी) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के डीजी के नेतृत्व में दोनों पक्षों के बीच ये वार्ता होगी। भारत ने इन वार्ताओं के लिए दो तिथियों का प्रस्ताव दिया है, एक इस महीने के अंत में और दूसरी अक्टूबर के लिए। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेशी पक्ष ने संकेत दिया है कि वे बाद की तिथि चुन सकते हैं और आगमन और वापसी के दिनों सहित लगभग चार-पांच दिनों के लिए भारत की यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों अनुसार आगामी बैठक व्यापक सीमा प्रबंधन, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने, सीमा पर वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने में आपसी समन्वय और बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों से संबंधित पारंपरिक मुद्दों और विषयों पर आयोजित की जाएगी, जो बैठक की रूपरेखा तय कर सकते हैं। बता दें कि बीएसएफ देश के पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय भारतीय सीमा की रक्षा करता है। ये वार्ता बीएसएफ और बीजीबी के बीच डीजी-स्तरीय वार्ता का 55वां संस्करण होगा, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मादक पदार्थ निरोधक, सीमा शुल्क और दोनों देशों की कुछ अन्य संघीय एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे, जिनकी सीमा प्रबंधन में हिस्सेदारी है।

विनेश फोगाट की संभावित सीट पर 'जेलर' को लेकर क्यों खफा हुई कांग्रेस

नए भाजपाई को बचा सकेंगे 'बाबा'!

नई दिल्ली। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ये दोनों पहलवान, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। विनेश फोगाट के लिए संभावित सीट, दादरी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने यहां पर सुनील सांगवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। विनेश फोगाट की संभावित सीट पर जेलर यानी सुनील सांगवान को लेकर कांग्रेस पार्टी खफा हो गई है। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कौन इतना नादान है जो इस खबर से हैरान हैं?। उन्होंने अपनी पोस्ट में दादरी सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान और एक बाबा का जिक्र भी कर दिया। इसके बाद प्रदेश की सियासत में यह चर्चा होने लगी कि क्या वह बाबा, चुनावी दंगल में नए भाजपाई एवं पूर्व जेलर को बचा सकेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी हॉट सीट मानी जा रही है। ये अलग बात है कि अभी यहां से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। 2019 में सोमबीर सांगवान, चरखी-दादरी सीट पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। जजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सतपाल सांगवान को 29577 वोट मिले थे। वे दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा प्रत्याशी एवं दंगल गर्ल बबीता फोगाट को 24 हजार 786 वोट मिले थे। वे तीसरे नंबर पर रहीं। अब सतपाल सांगवान भाजपा में हैं। पिछले दिनों उनके पुत्र सुनील सांगवान, जो हरियाणा सरकार में जेलर जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, एकाएक उन्होंने स्वैछिक सेवानिवृत्ति 'वीआरएस' ले ली। इतना ही नहीं, सुनील सांगवान ने भाजपा भी वाइन कर ली थी।

प्रदेश की राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस बार भाजपा को दादरी से बबीता फोगाट, यादा मजबूत प्रत्याशी नजर नहीं आ रही थीं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी यह बात सामने आई थी। मौजूदा परिस्थितियों में अगर विनेश फोगाट, दादरी से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ती हैं तो बबीता, मुसीबत में फंस सकती थीं। यही वजह है कि भाजपा ने इस बार दादरी से सुनील सांगवान को तैयार किया है। बुधवार को भाजपा की पहली सूची में उन्हें टिकट दे दी गई है। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान, हरियाणा में मंत्री रहे चुके हैं। उनका दादरी सीट पर खासा प्रभाव माना जाता है।

कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा एक्स पर लिखी गई पोस्ट ने सिसायत गर्मा दी है। श्रीनेत ने कौन इतना नादान है जो इस खबर से हैरान हैं? के साथ सुनील सांगवान का एक फोटो भी शेयर किया है। इस फोटो पर लिखा है, अपने कार्यकाल में छह बार राम रहिम को रिहाई देने वाले जेलर सुनील सांगवान भाजपा में शामिल। बता दें कि रोहतक की सुनारियां जेल में बंद राम रहिम को इस साल कई बार पैरोल मिल चुकी है। जब भी उन्हें पैरोल मिलती है तो वह मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के

कार्यकाल के दौरान भी राम रहिम को कई बार पैरोल दी गई थी। अब सीएम नायब सैनी के कार्यकाल में भी उन्हें पैरोल मिल रही है। चूंकि अब सुनील सांगवान, वीआरएस ले चुके हैं और उन्होंने भाजपा, वाइन कर ली है। अब उन्हें टिकट भी मिल गई है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि क्या बाबा, सुनील सांगवान की चुनावी दंगल में मदद कर पाएंगे।

यूस, यूके जैसे देश रह गए पीछे, क्लाइमेट फायनेंस में भारत का दिखा दम,

नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम स्थित थिंक टैंक ओडीआई और ज्यूरिख क्लाइमेट रेजिलिएंस अलायंस की तरफ से जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जलवायु वित्त कई विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा है। एक नए विश्लेषण के अनुसार, भारत ने 2022 में बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के माध्यम से जलवायु वित्त में 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ये आंकड़ा कई विकसित देशों के योगदान से कहीं ज्यादा है। यूके स्थित थिंक टैंक ओडीआई और ज्यूरिख क्लाइमेट रेजिलिएंस एलायंस द्वारा आयोजित विश्लेषण, चीन और सऊदी अरब जैसे विकासशील देशों को शामिल करने के लिए जलवायु वित्त के लिए दाता आधार को व्यापक बनाने के लिए कुछ विकसित देशों द्वारा नए सिरे से दबाव डालने के बीच

सबसे ज्यादा फंड देने वाला देश बना आया है।

केवल 12 देश ही प्रदान कर रहे उचित हिस्सेदारी - रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 12 विकसित देशों ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में अपना उचित हिस्सा प्रदान किया। ये देश नॉर्वे, फ्रांस, लक्ज़मबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और फिनलैंड हैं। रिसचर्स ने दावा किया कि जलवायु वित्त में महत्वपूर्ण अंतर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका अपना उचित योगदान देने में विफल रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने भी इस संबंध में अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन किया। विश्लेषण ने शीर्ष 30 गैर-अनुलग्नक-।। देशों की पहचान की है जिन्होंने विकास बैंकों और जलवायु निधियों में बहुपक्षीय योगदान के माध्यम से 2022 में विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त प्रदान किया है। इस समूह में पोलैंड और रूस जैसी संक्रमणकालीन पूर्व अर्थव्यवस्थाएं, 1992 से उच्च आय का दर्जा हासिल करने वाले देश जैसे चिली, कुवैत, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया और ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, फिलीपींस और पाकिस्तान सहित बड़ी आबादी वाले मध्यम आय वाले देश शामिल हैं।

भारत ने कितना योगदान दिया?

रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 में बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के माध्यम से जलवायु वित्त में 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो कई विकसित देशों के योगदान से अधिक है। ये ग्रीस (0.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर), पुर्तगाल (0.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर), आयरलैंड (0.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) न्यूज़ीलैंड (USD 0.27 बिलियन) जैसे कुछ विकसित देशों द्वारा दिए गए योगदान से कहीं अधिक है।

कांटे की लड़ाई भाजपा ने मारी बाजी, 7 सीटों पर किया कब्जा, आप को सिर्फ 5 सीटें

नई दिल्ली। दिल्ली एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। पार्टी ने 12 में से 7 जोन जीते। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने 5 वार्ड समितियों में जीत हासिल की। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) वार्ड समिति के चुनाव बुधवार को एजेंसी मुख्यालय में भारी सुरक्षा तैनाती के साथ शुरू हुए। लंबे समय से लंबित ये चुनाव 2022 में एमसीडी के एकीकरण के बाद पहली बार हो रहे थे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक गतिरोध के कारण चुनाव में देरी हुई है और यह अब तक अदालत में विचाराधीन है। भाजपा ने जोनल स्तर की वार्ड समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 12 में से सात क्षेत्रों में स्थायी समिति के लिए एक-एक सदस्य का पद हासिल किया, जिससे आप बेहद कड़े मुकाबले में पांच क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई। बीजेपी ने नरेला, सिविल लाइंस, केशव पुरम, शाहदरा नॉर्थ, नजफगढ़, शाहदरा साउथ और सेंट्रल जोन जीते, जबकि 'आप' ने करोल बाग, वेस्ट, साउथ, सिटी एसपी और रोहिणी जोन जीते। हाल ही में 'आप' से भाजपा में आए पार्षद पवन सहरावत और सुगंधा ने क्रमशः नरेला और सेंट्रल जोन से वार्ड समितियों के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। सिविल लाइंस क्षेत्र में आप और भाजपा के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई और भगवा पार्टी ने सभी तीन पदों पर एक-एक वोट के अंतर से जीत हासिल की। अनिल कुमार त्यागी ने अजीत सिंह यादव को 10 वोटों से हराया, जबकि रेखा ने अपने प्रतिद्वंद्वी गगन चौधरी को इसी तरह हराया। उत्तरी दिल्ली के पूर्व मेयर और एमसीडी में विपक्ष के भाजपा नेता राजा इकबाल सिंह ने आप की प्रोमिला गुप्ता को नौ वोटों के मुकाबले 10 वोटों से हराया। करोल बाग जोन में, 'आप' पार्षद राकेश जोशी को वार्ड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया, जबकि ज्योति गौतम और अंकुश नारंग को किसी भी भाजपा उम्मीदवार की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्य का पद मिला। भाजपा के किसी भी उम्मीदवार की अनुपस्थिति में आप उम्मीदवार मोहम्मद सादिक, किरण बाला और पुनरदीप सिंह साहनी को सिटी एसपी जोन से वार्ड समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया।

प्रमुख समाचार

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस से कुछ इस अंदाज में मिले मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सिंगापुर पहुंचते ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि भारत-सिंगापुर मित्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होने वाली विभिन्न बैठकों का इंतजार कर रहा हूं। भारत के सुधार और हमारी युवा शक्ति की प्रतिभा हमारे देश को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाती है। हम घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों की भी आशा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सिंगापुर पहुंचे। गृह मंत्री और विधि मंत्री के शनमुगम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आगे बहुत व्यस्तता वाला एजेंडा है। मोदी का बृहस्पतिवार को संसद भवन में आधिकारिक स्वागत किया जाएगा और वह सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से मुलाकात करेंगे। वोंग ने कुछ दिन पहले ही सत्ता संभाली है और मोदी ने भी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है।

बंगाल में लोगों ने बत्ती बुझा कर किया प्रदर्शन

कोलकाता। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्याकांड का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। चिकित्सकों के साथ आम लोगों ने भी जोर-शोर से इस मामले में किए जा रहे आंदोलनों में हिस्सा लिया है। बुधवार को लोगों ने बंगाल की सड़कों पर अलग-अलग क्षेत्रों में बत्तियां बुझा कर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ अब प्रदर्शनों में पहली बार मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने भी हिस्सा लिया है। मृतका के पिता ने बुधवार को कहा कि हमें इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेना ही होगा। आखिर हम और कर भी क्या सकते हैं? चीजें बहुत धीरे-धीरे हो रही हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे सवाल हैं और हम सब कुछ पुलिस से पूछेंगे। इस घटना पर सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने सड़कों पर बत्ती बुझा कर प्रदर्शन किया। खासकर कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से लेकर श्याम बाजार और विक्टोरिया मेमोरियल तक की बत्तियां बंद कर प्रदर्शन किया गया। रात नौ बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मोमबत्तियां और मोबाइल के फ्लैश लाइट के सहारे जुलूस निकाले।

उत्तराखंड के सीएम को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकार के प्रमुखों से पुराने जमाने के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती और हम सामंती युग में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया कि उन्होंने राज्य के वन मंत्री और अन्य की लोगों राय की अनदेखी करते हुए एक भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक कैसे नियुक्त किया। हालांकि, राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी को टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने का आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक आईएफएस अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त किये जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही इस पीठ में न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम अधिकारी की ओर से एक विशेष टिप्पणी थी।

कोरोना महामारी के दौरान दी गई खराब वैक्सीनः सोरेन

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आरोप लगाया कि कोविड-19 के दौरान दिए गए खराब टीकों के कारण लोगों की अब भी मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि एक विशेष टीके की भारत में अभी भी आपूर्ति की जा रही है, जो दुनियाभर में प्रतिबंधित है और इसे लोगों को दिया जा रहा है। सोरेन का यह बयान राज्य में हाल ही में आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान 12 लोगों की मौत के बाद आया। सरकार ने सोमवार को इस भर्ती पर तीन दिन के लिए रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा, भर्ती अभियान के दौरान दुर्भाग्य से कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई। ये मौतें केवल दौड़ने के कारण नहीं हो रही हैं, बल्कि लोग चलने के दौरान भी मर रहे हैं। यह सभी को पता है कि कोरोना महामारी के दौरान भाजपा सरकार की ओर दिए गए टीके खराब थे और इसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा था। पहले झारखंड भाजपा ने इन मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेते हुए सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए।

राजस्थान-जैसलमेर सीमा पर भी दिखेगा अब वाघा बॉर्डर वाला नजारा

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पंजाब के अमृतसर में वाघा सीमा पर प्रतिदिन आयोजित होने वाले समारोह की तर्ज पर राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू करेगा। तनोट राय माता मंदिर परिसर में इस उद्देश्य के लिए 1,000 लोगों की क्षमता वाला एक एम्फीथिएटर निर्माणाधीन था। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक (जैसलमेर) योगेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बीएसएफ कर्मी हर शाम ऊंट शो और अन्य कार्यक्रमों के साथ भारतीय ध्वज को नीचे उतारेंगे। हालांकि वाघा अटारी की तरह पाकिस्तानी पक्ष में ऐसा कोई समारोह आयोजित किए जाने की जानकारी नहीं है। तनोट के पास बबलियान सीमा चौकी को पहले सरकार की सीमा पर्यटन पहल के तहत 2021 में रिट्रीट समारोह के लिए विकसित किया गया था। समारोह के लिए तनोट को चुने जाने से पहले 2022 तक साइट पर एक स्टेडियम, वॉचटावर, सेल्फी पॉइंट आदि का निर्माण किया गया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पिछले साल सीमा पर्यटन पहल के तहत तनोट परिसर के विकास के लिए रु. 17.67 करोड़ मंजूर किए थे। बीएसएफ ने अब तक 70 फीसदी काम पूरा कर लिया है। 4.57 एकड़ में फैले परिसर में 434 वर्ग मीटर का कैफेटेरिया, 183 वर्ग मीटर का वीआईपी ब्लॉक, एक स्मारिका दुकान और एम्फीथिएटर के साथ एक शौचालय ब्लॉक भी शामिल होगा।

सेना को सप्लाई किए जा रहे ड्रोन में चीनी पार्ट्स रोकने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी

भारत 2030 तक ड्रोन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल ड्रोन हब के तौर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपने को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियां पूरे जी जान से जुटी हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब सेना में नए-नए तरह के ड्रोन शामिल किए जाने की खबरें न आती हों। अदाणी, टाटा, रिलायंस जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों समेत कई स्टार्पअप्स भी मिलिट्री ड्रोन बनाने में जुट गए हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन ड्रोन में चाइनीज पार्ट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। जिसे लेकर भारतीय सेना भी सचेत हो गई है। भारतीय सेना के लिए चिंता की बात यह है कि निजी कंपनियों से हासिल किए गए ज्यादातर ड्रोनों को देश की पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया गया है। वहीं, सेना अब स्वदेशी ड्रोन में चीनी पार्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कड़ी नीति बनाने की तैयारी कर रही है।

सीक्रेट डाटा का खतरा

इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि मिलिट्री इस्तेमाल के लिए देश में बनाए जा रहे अधिकांश ड्रोनों में चीनी पार्ट्स का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इनमें चिप और हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी हैं, जिन्हें चीन में बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें सभी प्रकार के लॉजिस्टिक ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन और सर्विलांस ड्रोन भी शामिल हैं। सेना के लिए चिंता की बात यह है कि खरीदे गए ज्यादातर ड्रोन को संवेदनशील चीनी सीमा पर तैनात किया गया है और सेना का सीक्रेट डाटा चीनी हाथों में पड़ने का बड़ा जोखिम है। जिसे देखते हुए सेना और रक्षा मंत्रालय ने ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्ररर को ब्लैक लिस्ट भी किया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लॉजिस्टिक ड्रोन बनाने वाली एक भारतीय कंपनी के 200 ड्रोन के ऑर्डर पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा सेना उस सभी कंपनियों के ड्रोन की जांच भी कर रही है, जिन्हें हाल ही में खरीदा गया है। साथ ही, सेना भी अब ऐसे मामले आने के बाद सचेत हो गई है और उन्हें सप्लाई किए जाने वाले ड्रोन में चीनी पार्ट्स को लेकर %खास मैकेनिज्म% बनाने की तैयारी कर रही है।

बच जाती हैं कंपनियां

आर्मी डिजाइन ब्यूरो (एडीबी) के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल सीएस मान ने इसे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा, हमें इस बात की जानकारी है और सरकार ने भी पिछले दिनों इस पर कुछ कार्रवाई भी की है। हम ऐसे तरीके खोज रहे हैं, जिससे चीनी पार्ट्स का पता लगाया जा सके। ताकि सुरक्षा को देखते हुए ऐसी कंपनियों को अनुमति देने से रोका जा सके।

बता दें कि रक्षा खरीद में चीनी पार्ट्स के

इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में चीनी पार्ट्स न होने को लेकर सेल्फ सर्टिफिकेशन देती हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स में चाइनीज पार्ट्स की जांच का कोई तरीका न होने के चलते उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मेजर जनरल मान ने बताया कि इस पर विचार-विमर्श जारी है। हम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के साथ मिल कर काम कर रहे हैं और जल्द ही चीनी पार्ट्स की पहचान करने के लिए उचित तरीका लागू किया जाएगा। हालांकि यह कब से लागू होगा, उन्होंने इसकी कोई समयसीमा नहीं बताई।

पता लगाना बेहद मुश्किल

वहीं फिक्की डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी के उपाध्यक्ष आशीष कंसल ने बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस संदर्भ में चीन से हम कोई पार्ट्स न खरीदें। लेकिन हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, और यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि वह पार्ट चीन से अमेरिका चला जाए और वहां से भारत आ जाए। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि चीन से ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भारत में न आए। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और चिप जैसे पार्ट्स अब हम यहां खुद ही बना रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय ने दी थी चेतावनी

ड्रोन में चीनी पार्ट्स लगे होने का मामला तब सामने आया जब रक्षा मंत्रालय ने 25 जून को उद्योग संगठनों को पत्र जारी करके भारत में ड्रोन निर्माण में चीनी पार्ट्स के इस्तेमाल होने की बात कही। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन (डीडीपी) ने फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) को एक पत्र लिख कर ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने लॉजिस्टिक ड्रोन बनाने वाली एक भारतीय कंपनी के 200 ड्रोन के ऑर्डर पर भी रोक लगा दी। हालांकि उस कंपनी का कहना है कि उनके ड्रोन में चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डीडीपी ने अपने पत्र में तीन कंपनियों का भी जिक्र किया और उद्योग संगठनों से कहा कि वे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने वाले मैंबर्स से कहें कि वे इस तीन कंपनियों से डिफेंस सामान खरीदते समय सावधानी बरतें।

इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते पिछले कुछ समय से मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की सप्लाई बढ़ गई है।

लाल आतंक पर जोरदार प्रहार, मारे गए नौ नक्सलियों के शव बरामद

■ भारी संख्या में मिले हथियार

दंतेवाड़ा। छत्तीगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद भारी संख्या में हथियार और मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। कल हुई मुठभेड़ में जवानों ने नौ नक्सलियों को ढेर कर दिया था। पश्चिम बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। तीन सितंबर को सुबह सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों से हुआ तभी गोलीबारी के दौरान नौ माओवादी मारे गए।

मिली जानकारी के मुताबिक जंगली इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की पुलिस ने अन्य सुरक्षाबलों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया था।

दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में अब तक 09 नक्सलियों के मारे जाने के साथ ही बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों द्वारा 13 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर प्राप्त हुई है। निश्चित ही यह सुरक्षाबल के जवानों के लिए बड़ी सफलता है। मैं इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों, जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं और बधाई देता हूं। नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। मुठभेड़ में नौ नक्सलियों के मारे जाने के बाद प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये जवानों की ताकत है, बस्तर विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने वाला है।

इससे पहले 29 अगस्त को भी नारायणपुर-कांकेर बॉर्डर पर नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई थी जिसमें सुरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया था। अगस्त की शुरुआत में भी दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी। मुठभेड़ में एक हार्डकोर नकस्ली मारा गया था। साथ ही, हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए थे। इसके लिए जवान बारिश के मौसम में उफनती इंद्रावती नदी को पार कर नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचे थे।

लाल आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षाबलों ने संभाला मोर्चा

नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। फोर्स बस्तर संभाग में डेरा जमाए हुए है। नक्सलियों की मांद में घुसकर उनसे टक्कर ले रही है। बस्तर में मानसून सीजन के बीच फोर्स के जवान डटे हुये हैं और नक्ससियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर की मनमोहक और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से लाल आतंक के साये को खत्म करने के लिए बस्तर संभाग में फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है।

देवेंद्र सेठिया के नाम पर धोबीगुड़ा का प्रायमरी स्कूल
नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में हुए थे शहीद

जगदलपुर। बस्तर जिले के धोबीगुड़ा में जन्म लेने वाले देवेन्द्र सेठिया का अप्रैल माह में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, जिसके 5 माह बाद गृहग्राम में बने प्रायमरी स्कूल का नामकरण शहीद देवेंद्र कुमार सेठिया के नाम से किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ ही परिवार के लोग भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के ग्राम गलगम में एक सीआरपीएफ की पार्टी 19 अप्रैल 2024 एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी, इसी दौरान यूबीजीएल ब्लास्ट होने से कॉस्टेबल देवेंद्र के पैर, कमर और हाथ मे गंभीर चोट आई, जिसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए मेकाज हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा गया। मेकाज पहुँचने से पहले देवेंद्र सेठिया शहीद हो गए थे। शहीद देवेंद्र सेठिया के गृहग्राम धोबीगुड़ा में 4 सितंबर की सुबह सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के मौजूदगी में पहले प्रायमरी स्कूल ग्राम धोबीगुड़ा में शहीद जवान के छायाचित्र पर पूरे सम्मान के साथ पहले पुष्पगुच्छ अर्पित करने के बाद भारत माता के जयकारे के नारे लगाए गए, उसके बाद स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखा गया। शहीद कांस्टेबल देवेन्द्र सेठिया के परिजनों ने बताया कि वर्ष 2013 में देवेंद्र ने सीआरपीएफ ज्वाइन किया था, उसके बाद कई वर्ष तक असम में पदस्थ रहने के बाद करीब 2 वर्ष पहले भद्राचलम में सीआरपीएफ बटालियन में रहने के बाद करीब 8 माह पहले 196 बटालियन बीजापुर गया, जनवरी में दियारी त्यौहार होने के कारण करीब 1 माह की छुट्टी लेकर आया हुआ था, फिर वापस अपने ड्यूटी बीजापुर चला गया, 19 अप्रैल की करीब सुबह 3 बजे अपने छोटे भाई योगेंद्र को फोन पर जन्मदिन का संदेश भी भेजा उज़के बाद अपने साथियो के साथ सर्चिंग में चला गया।

दंतैल हाथी की फिर हुई वापसी
पाली रेंज में कर रहा विचरण

कई किसानों की फसलों को किया बर्बाद

कोरबा। कोरबा में तांडव मचाने के साथ ही नी लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले दंतैल हाथी एक बार फिर से कोरबा पहुंच गया है। चांप-जांजगीर और बिलासपुर जिले में ग्रामीणों को दहशत में डालने वाला हाथी पाली क्षेत्र में विचरण कर रहा है। हाथी डोंगानाला,गणेश पुल और मुनगाडीह गांव में किसानों की फसलों को रौंद चुका है। वन विभाग ग्रामीणों को सचेत रहने को कहा है।

कोरबा जिले में जंगली हाथी दहात का पर्याय बन चुके है। हाथी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हाथियों के कारण जान माल का नुकसान लगातार जारी है। पिछले माह तीन लोगों की जान लेकर पहले चांपा जांजगीर फिर बिलासपुर जिले का रुख करने वाला दंतैल हाथी एक बार फिर से कोरबा पहुंच गया और कटघोरा वनमंडल के पाली रेंज में विचरण कर रहा है। हाथी ने हाल ही में डोंगानाला,गणेश पुल,मुनगाडीह गांव में जमकर तबाही मचाई हैं। कई किसानों की फैसलों को बबार्द कर चुका हाथी ईलाके में विचरण कर रहा है,जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग हाथी पर नजर जमाए हुए है और लोगों को उसके करीब नहीं जाने की सलाह दे रहा है।

रेंजर पाली रेंजर संजय लकड़ा ने बताया कि वन विभाग हाथी द्वारा किए गए नुकसान का आंकलन कर रहा है ताकी प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जा सके। दिन रात विभाग के कर्मचारी हाथी के विचरण पर नजर रखे हुए हैं ताकी कोई अनहोनी ना हो पाए।

फिर सामने आई आदिवासी विकास विभाग की लापरवाही

■ नहीं मिल रहा समय से खाना

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में आदिवासी विकास विभाग की लापरवाही और अव्यवस्था की बानगी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विभाग द्वारा संचालित 50 सीटर आदिवासी आश्रम शाला नेवरी के बच्चे रात 9:00 बजे तक भूखे रह गए, भूखे बच्चों को देखकर गांव के पंच सरपंच ने मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी, जिसके बाद दूसरे छात्रावास से गैस सिलेंडर पहुंचा तब कहीं जाकर बच्चों को दाल चावल और आचार का भोजन मिल सका।

वहीं छात्रावास के रसोईया और चौकीदार ड्यूटी टाइम में भी छात्रावास में शराब के नशे में धुत होने का आरोप अधीक्षक सहित ग्रमीणों और छात्रों ने लगाया... जबकि 50 सीटर छात्रावास से 37 छात्र रात में छात्रावास से गायब मिले, अव्यवस्था लापरवाही और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका आदिवासी विकास विभाग में जो अव्यवस्था सामने आई जो पूरे विभाग के मुंह पर कालिख की तरह है गौरेला विकासखंड अंतर्गत वन क्षेत्र में संचालित नेवरी बालक आश्रम छात्रावास के छात्र रात 9:00 बजे तक भूखे रह गए, भूखे रहने की वजह जिम्मेदारों की लापरवाही है।

छात्रावास में कुकिंग गैस सिलेंडर एक दिन पहले ही शाम को खत्म हो गया जिसकी सुध किसी ने नहीं ली, इस वजह से रात को भोजन ही नहीं बन सका, भूख से बिलबिलाते मासूम छात्र-छात्रावास परिसर में मुंह लटकाए घूम रहे थे जिन्हें देखकर ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने छात्रों से पूछा तब छात्रों ने अपनी व्यथा बताई कि आज उन्हें भोजन ही नहीं मिला है, जिस पर गांव के पंच सरपंच मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी, इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, पर जिम्मेदार आदिवासी विकास विभाग की लापरवाही देखिए 50 सीटर छात्रावास के छात्र भूखे पड़े रहे पर किसी भी अधिकारी ने रात में छात्रावास पहुंचने या जांच करने या व्यवस्था दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि एक दूसरे छात्रावास के अधीक्षकों को निर्देशित कर दिया कि वहां गैस सिलेंडर पहुंचा दे इसके बाद दूसरे छात्रावास से अधीक्षक रात में गैस सिलेंडर लेकर पहुँचे तब दाल चावल बना और तब कहीं जाकर छात्रावास के छात्र भोजन कर सके। शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार रात छात्रों को चावल के साथ बेसन की कढ़ी और आलू की सूखी सब्जी मिलनी चाहिए थी, पर बच्चों को जो दाल चावल नसीब हुआ वही उनके लिए सौभाग्य की बात थी 15 जून के बाद से नए शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के बाद ढाई महीने में किसी भी अधिकारी ने इसकी ना तो शिकायत की ना ही इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई , जो यह साबित करता है कि विभाग इस गोरख धंधे में पूरी तरह संलिप्त है अब नव निहालों का भविष्य बनाने के लिए शुरू किए गए इस आश्रम शाला की दूसरी अव्यवस्था भी समझ ली जाए वैसे तो छात्रावास में अधीक्षक सहित कुल 6 कर्मचारी हैं पर मौके पर अधीक्षक के साथ एक ही कर्मचारी मिला वह भी शराब पिए हुए था जो हमे देख कर अंधेरे में भाग गया और उसके शराब पीने की पुष्टि छात्रवासी छात्रों के साथ ग्रामीणों और अधीक्षक ने भी करी, छात्रों ने यहां तक बताया कि दोनों कर्मचारियों शराब पीकर भोजन बनाते हैं, अब यदि छात्रावास में कर्मचारी शराब पिए हुए रहेंगे तो जाहिर है भविष्य में छात्र शराब की भी आकृष्ट हो जाए तो कोई अचम्भा नहीं है। आदिवासियों के भविष्य को सुधारने के लिए बनाया गया आदिवासी विकास विभाग पूरी तरह अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुका है, ऐसे में कर्मचारी शराब पीकर छात्रावास में रहे या 50 सीटर छात्रावास में 13 बच्चे उपस्थित रहे यह बच्चे रात भर भूखे रहे विभाग मूकदर्शक बनकर सिर्फ तमाशा ही देख रहा है।

1 जनवरी से पैसेंजर, मेमू, लोकल ट्रेनें सामान्य ट्रेनों के रूप में नियमित चलेगी

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मेमू और पैसेंजर ट्रेनों पर सुनवाई

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के डीआरएम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में इस बात की जानकारी दी कि पैसेंजर, मेमू लोकल ट्रेनों को 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। शपथ पत्र में बताया गया कि पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को 1 जुलाई 2024 से सामान्य ट्रेन के रूप में चलना था लेकिन रेलवे टाइम टेबल ना छपने के कारण ट्रेनें के परिचालन में देरी हुई।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की खंडपीठ में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव कि उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कोविड के बाद से रेलों के अव्यवस्थित चलने और पैसेंजर गाड़ियों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने और लेट लतीफी को मुद्दा बनाया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीआरएम को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था। डीआरएम के शपथ पत्र में यह बताया गया कि भले ही मेमू लोकल, स्पेशल ट्रेन के रूप में चले लेकिन उनमें स्पेशल ट्रेन का चार्ज नहीं वसूला जाएगा।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यात्रियों को होने वाली परेशानी पर याचिका

20 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने यह जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा किया गया कि अभी भी पैसेंजर और मेमू लोकल ट्रेन, स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनों के संबंध में कोई समयबद्धता रिपोर्ट नहीं भेजी जाती इसलिए रेलवे का ऑपरेटिव विभाग स्पेशल के रूप में चल रही मेमू लोकल ट्रेनों को आउटरों पर लंबे समय तक खड़ा रख दिया जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। इसके अलावा इन स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने के लिए भी कोई उच्च स्तरीय अप्रूवल नहीं लगता।

इस स्थिति को जानकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बिलासपुर के डीआरएम को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। शपथ पत्र के माध्यम से रेलवे के द्वारा बताया गया कि इस साल का टाइम टेबल ना छाप पाने के कारण यह पैसेंजर और लोकल ट्रेन अभी भी स्पेशल के रूप में चल रही हैं। 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि टाइम टेबल छपने से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह ट्रेनें सामान्य ट्रेनों के रूप में अभी भी चलाई जा सकती है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी कि रेलवे ने गेवरा रोड रायपुर के बीच चलने वाली 08745 और 08746 मेमू लोकल को पिछले 9 महीने से रद्द कर दिया है। इस पर भी हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश लेकर परिचालन की बात कही। याचिकाकर्ता को इस छूट के साथ कि भविष्य में कोई जन समस्या होने पर वह पुन: याचिका दाखिल कर सकते हैं, जनहित याचिका निराकृत कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

6 टीआई, 1 एसआई, 12 एएसआई सहित 273 आरक्षकों का तबादला

भिलाई नगर। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जिले के सभी थानों में पदस्थ प्रभारी रैंक से लेकर आरक्षक तक का तबादला आदेश जारी किया है जिस में 6 टीआई, एक एसआई, 12 एएसआई तथा 273 आरक्षकों को एक थाने से दूसरे जगह भेजा गया है। जारी तबादला आदेश के मुताबिक निरीक्षक राजेश साहू को उजेवरा सिरसा चौकी से भट्ठी थाने का प्रभारी, निरीक्षक वंदिता पानिकर को खुर्सीपार थाने से हटाकर स्मृति नगर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक अंबिका प्रसाद ध्रुव को जामगांव आर से पदमनाभपुर, अंबर सिंह भारद्वाज को पद्मनाभपुर से खुर्सीपार, प्रशांत मिश्रा भट्ठी से भिलाई नगर, राज कुमार लहरे को भिलाई नगर से जामगांव आर भेजा गया है। स्मृति नगर चौकी में पदस्थ उपनिरीक्षक पुरषोत्तम कुर्रे को जेवरा सिरसा चौकी का प्रभारी बनाया गया है। पलिस लाइन में पदस्थ एएसआई प्रदीप तिवारी को सुपेला, राम कृष्ण तिवारी को थाना दुर्ग, विजय कुमार देशमुख को डीसीआरबी, प्रेमचंद यादव को पदस्थ किया गया है।

600 सीसीटीवी खंगालने के बाद मिला चोरी का सरगना

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा पुलिस ने मंदिर की दान पेटी चोरी मामले को सुलझाने मे सफलता हासिल की है। पुलिस ने बिलासपुर से चार आरोपियो को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 37 हजार रुपये कैश और घटना मे उपयोग किए गए औजार को बरामद किया है। सभी आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं। 3 आरोपी आदतन अपराधी है। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने प्रेसवार्ता कर बताया- 25 अगस्त को नहरिया बाबा मंदिर में चोरों ने दानपेटी की चोरी की थी। जांच के दौरान पता चला कि घटना स्थल से चोरों ने बाइक भी चुराई थी। बाइक से उनके संभावित भागने के रास्ते के बारे में पता चला। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बालोद होते हुए बिलासपुर जाने का खुलासा हुआ। जिसके बाद पता चला कि धीरेन्द्र ऊर्फ टिंकू वैष्णव के बारे में पता चला। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर विजय कुमार वैष्णव और रामायण केवट को पकड़ा गया। उनके पास से 36 हजार रुपये बरामद किए। बाइक भी बरामद की गई।

अब प्राइमरी, मिडिल स्कूल के शिक्षक बना रहे आयुष्मान कार्ड

कोरबा। छत्तीसगढ़ में अब आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शिक्षकों को दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक मोबाइल एप जारी किया है। शिक्षकों को यह एप उनके मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। इसी एप के जरिए शिक्षक डिटेल्स आयुष्मान कार्ड के वेबसाइट पर फीड करेंगे। फिर वहीं से आयुष्मान कार्ड जारी करेंगे। कोरबा जिले के ज्यादातर स्कूलों में इसका काम शुरू हो चुका है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड ले जाने पर स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान कार्ड बन जाता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परमानेंट आयुष्मान कार्ड काउंटर है। यहां से लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं निजी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी जाती है। निजी अस्पतालों में इसके लिए एक काउंटर मौजूद रहता है। लेकिन अब आयुष्मान कार्ड बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। शासन के आदेश के बाद शिक्षकों ने काम करना शुरू कर दिया है।

स्वाइन फ्लू से 59 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत

महासमुंद। जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनमें 4 मरीज स्वस्थ चुके है और एक मरीज होम आइसुलेशन में है। वहीं एक 59 वर्षीय मरीज की इलाज के दौरान राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में मौत हो गई है। जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ छत्रपाल चंद्राकर ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट करते हुए लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ छत्रपाल चंद्राकर ने बताया कि कल सुबह रायपुर के निजी अस्पताल में बसना के 59 वर्षीय एक व्यक्ति की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हुई है। वहीं जिले में स्वाइन फ्लू के 7 मरीज पाए गए है जिनमें से 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं महासमुंद के 01 मरीज का होम आइसुलेशन में इलाज जारी है। बसना के 01 और मरीज का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पॉजिटिव मरीजों का कांटेक्ट ट्रेसिंग किया गया है। हालांकि जो व्यक्ति स्वाइन फ्लू पॉजीटिव पाए गए हैं उनके कांटेक्ट में आने वाले अन्य कोई भी व्यक्ति, स्वाइन फ्लू के लक्षण में नहीं है।

सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, गहने व नकदी पार

कोरबा। कोरबा में मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत दादर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सुने मकान का ताला तोड़कर चोर डेढ़ लाख कीमती सोने के जेवरात और नगदी रकम ले भागे। घटना की सूचना पर मानिकपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की गई। जहां आरोपी को पकड़ने पुलिस डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। सीएसईबी रिटायर्ड कर्मी रामेश्वर प्रसाद साहू दादर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एलआईजी 9 में पिछले कुछ सालों से रिटायर्ड होने के बाद अपने पत्नी के साथ रहता है वही उसके बच्चे और परिवार सीएसईबी कॉलोनी में रहते हैं। दो दिन पहले रामेश्वर प्रसाद साहू की पत्नी राम भाई साहू की तबीयत खराब होने पर उसे रायपुर लेकर गया हुआ है जहां उसका आज ऑपरेशन चल रहा है। घर की देखरेख करने के लिए पास में ही रहने वाले रिश्तेदार को चाबी दिया था रिश्तेदार रोज की तरह बुधवार की सुबह ताला खोलने घर पहुंचे ही थे कि सामने गेट का ताला टूटा हुआ था अंदर जाकर देखा तो बेडरूम और दो अन्य रूम का ताला भी टूटा हुआ था।

लापरवाही बरतने के कारण सहायक शिक्षक नीता एवं नरसिंह निलंबित

कोण्डागांव। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा जिले के कोण्डागांव विकासखण्ड अंतर्गत पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी श्रीमती नीता मण्डावी एवं श्री नरसिंह मण्डावी को कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं निलंबित उक्त दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के 02 सितम्बर सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान रात्रि में प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव परिसर स्थित आवासीय भवन अधीक्षिका निवास में प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती नीता मण्डावी के पति श्री नरसिंह मण्डावी को उपस्थित होना पाया गया। इस सम्बंध में छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित के प्रतिदिन रात्रि मंभ आने-जाने की पुष्टि भी की गई। चूंकि प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती नीता मण्डावी के पति श्री नरसिंह मण्डावी वर्तमान में बालक आश्रम कारसिंग में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत हैं। जबकि महिलाओं-बालिकाओं के संरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी समेकित कार्ययोजना के दिशा-निर्देश के तहत कन्या छात्रावास या आश्रमों में पुरुषों के प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंध लागू किये जाने के उपरांत भी श्रीमती नीता मण्डावी प्रभारी अधीक्षिका द्वारा श्री नरसिंह मण्डावी को रात्रिकालीन प्रवेश के लिए नहीं रोका जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत विपरीत होने से गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है, अतएव श्रीमती नीता मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी वर्तमान प्रभारी अधीक्षिका प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण-नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती नीता मण्डावी के पति श्री नरसिंह मण्डावी वर्तमान पदस्थापना सहायक शिक्षक एलबी बालक आश्रम कारसिंग की प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव में प्रतिदिन सुबह-शाम आने की पुष्टि सम्बन्धित प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव के कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इंद्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन है। सम्बन्धित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है और यह गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अतएव श्री नरसिंह मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी शासकीय बालक आश्रम शाला कारसिंग विकासखण्ड कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उक्त दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आजीविका मुहिम के लिए सरगीपाल में किया गया रबर प्लांटेशन

जगदलपुर। जिला प्रशासन की पहल पर रबर बोर्ड और उद्यानिकी विभाग के समन्वय से जिले में दस हजार पौधे का रबर के उत्पादन हेतु पौधारोपण किया जा रहा है। रबर के उत्पादन हेतु पौधारोपण का पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में सरगीपाल में आज बुधवार को किया गया । इसके लिए सभी विकासखंड में जमीन का चिन्हांकन किया गया है। कार्यक्रम में सरपंच चंपा नाग, जिला पंचायत सदस्य धरमूराम मंडावी ने संबोधित करते हुए कहा कि रबर प्लांटेशन को गांव की महिला समूह द्वारा सुरक्षित कर आगामी पांच साल बाद लाखों रुपए की आमदनी का जरिया बनेगा। रबर बोर्ड के अधिकारियों ने रबर की उत्पादन से होने वाले लाभ के बारे भी जानकारी दी।

कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि आजीविका का एक मुहिम के लिए रबर प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाने की पहल की जा रही है। बस्तर का वातावरण रबर प्लाटेशन के लिए उपयुक्त है, साथ ही सरकार की मंशा है रबर जैसे व्यावसायिक उत्पाद को बढ़ावा देना है। रबर की खेती में पौधे बड़े होने में लगभग पांच साल लगेंगे इसके बाद हर वर्ष लाखों की आमदनी होने की संभावना है, इसीलिए केंद्र सरकार की रबर बोर्ड इसके लिए भारत वर्ष में कार्य कर रही है। बस्तर में पिछले वर्ष डिलमिली क्षेत्र में और कृषि कॉलेज के परिसर में रबर प्लांटेशन किया गया। आज सरगीपाल के लगभग ढाई एकड़ जमीन में करीब 4 सौ पौधे का रोपण किया गया। गांव के चयनित जगह पर रबर पेड़ की खेती में ज्यादा से ज्यादा महिला समूह को जोडऩा है। इसके अलावा स्वतंत्र व्यक्ति भी अपने खेत रबर के पौधे भी लगा सकते है। पौधे बड़े होने पर इससे निकलने वाले रबर की खरीदी के लिये कम्पनियां आकर ले जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से कोसा निर्माता ने सौजन्य भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से बुधवार को यहां राजभवन में चांपा के कोसा वस्त्र निर्माता श्री चंद्रशेखर देवांगन ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के कोसा उद्योग और ककून से कोसा धागा करण की प्रक्रिया के साथ ही कोसा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया एवं मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी और राज्यपाल को कोसा से निर्मित शाल भेंट किया।

एसआई भर्ती परीक्षा रिजल्ट घोषित करने की मांग, गृहमंत्री के बंगले पहुंचे अभ्यर्थी

रायपुर। एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम को

लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोला है। एक बार फिर रैली की शक्ल में अभ्यर्थी गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले पर पहुंचे।इस दौरान गृहमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों को रोक दिया। सभी अभ्यर्थी गृहमंत्री से मिलने की जिद कर रहे थे।लेकिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा प्रवास पर होने के कारण उनसे नहीं मिल सके।लिहाजा अभ्यर्थियों को गृहमंत्री के बंगले के अंदर बिठाया गया है। सभी अभ्यर्थी हाल में बैठे डिप्टी सीएम विजय शर्मा का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अभ्यर्थियों के आने से कुछ देर पहले ही दुर्ग प्रवास पर गए हैं। इसलिए उनकी मुलाकात परीक्षार्थियों से नहीं हो सकी है। इससे पहले 28 अगस्त को एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम की मांग को लेकर गृहमंत्री निवास पर अभ्यर्थी पहुंचे थे।अभ्यर्थी दिनभर बंगले पर ही डटे रहे। आखिरकार रात को गृहमंत्री विजय शर्मा से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों की बात को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही ये वादा किया था कि वो 4 सितंबर को वापस लौटेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। लिहाजा अभ्यर्थी बुधवार को उनके मिलने के लिए आए थे।

महज घंटे भर की बारिश में दुकानों में घुसा पानी, व्यापारियों ने किया चक्काजाम

कांकेर। दुकानों में पानी घुसने से नाराज

व्यापारियों ने चक्काजाम किया। बार-बार अवगत करवाने के बाद भी शासन-प्रशासन पर ध्यान नहीं देने का आरोप है। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दरअसल, एक घंटे की मूसलाधार बारिश से नए बस स्टैंड के पास दुकानों में पानी घुस गया। नई सड़क से ऊंची नाली छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गई। पानी भरे होने की वजह से दुकान खोलने की स्थिति में नहीं है। बीते माह भी नाराज व्यापारियों ने चक्काजाम किया था। विधायक के आश्वासन के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी है।

छत्तीसगढ़ लौटे आईएएस अमित कटारिया, एक रुपये लेते थे सैलरी

रायपुर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी होने के बाद

आईएएस अधिकारी अमित कटारिया छत्तीसगढ़ वापस लौट आए हैं। आईएएस अफसर अमित कटारिया मंगलवार को मंत्रालय में अपनी ज्वाइनिंग दी। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात की। बात दें कि अमित कटारिया 2004 बैच के अधिकारी हैं। वे रायपुर और बस्तर में अहम पदों पर थे। 2017 से कटारिया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। इसके बाद एक बार फिर वे छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। नौकरी के शुरुआती दौर में आईएएस कटारिया केवल एक रुपए तनख्वाह लेते थे। आईएएस अधिकारी अमित कटारिया जितने दिन छत्तीसगढ़ में रहे चर्चा में ही रहे। अमित कटारिया 2016 में सुर्खियों में आए थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान काला चश्मा पहन रखा था। इस दौरान वे बस्तर में कलेक्टर के पद पर थे। इस घटना को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद से कटारिया चर्चा में रहे।

राज्यपाल डेका से अग्रवाल सभा के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने समाज की ओर से पुष्प-माला और शाल पहनाकर राज्यपाल का स्वागत किया और समाज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने हेतु उन्हें आमंत्रित किया। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के पदाधिकारी मनीष अग्रवाल, योगी अग्रवाल, राम अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, विकास अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल उपस्थित थे।

नियत समय में बनेंगे 18 लाख पीएम आवास योजना के घर : साय

■ केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी योजनाओं की सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 5 सालों तक जो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए थे, उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। पिछले 5 साल में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल उसके मुखिया थे तो प्रधानमंत्री आवास योजना से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। लेकिन अब हर गरीब के सिर पर छत होगी।

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- पीएम आवास के लिए 40 परसेंट राज्य सरकार को देना था लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह इसे देंगे तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम चल जाएग और इसका फायदा भाजपा और नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। इसलिए भूपेश सरकार ने पीएम आवास के लिए राशि नहीं दी। हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह राज्य में 18 लाख मुख्यमंत्री आवास बनाने का काम करेगा। इसी के क्रम में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है हमने पहले ही अपने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवास की स्वीकृति दे दी थी और 40 परसेंट जो राज्य का अंश होता है वह भी पैसा हमने इंतजाम करके दे दिया था। सीएम साय ने

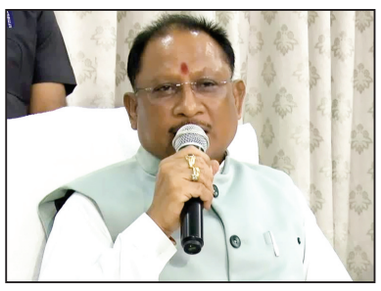

कहा- 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ के लिए कुल 846931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। मुख्यमंत्री ने कहा हम लोगों ने 18 लाख आवास की बात की है, जिसमें से जो लोग वंचित हो गए थे, उसमें से 699000 आवास 2011 वाली सूची में से है। बाकी 147600 आवास प्लस योजना के तहत हैं। इसके लिए विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 24064 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। साय ने आगे कहा- पिछली सरकार ने 47 हजार 90 आवासों के लिए जो पैसा जारी किया था, उसके बाद के बचे हुए पैसे को हम लोगों ने जारी कर दिया है। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जिन लोगों को भी आवास मिला था उन्हें पैसा आवंटित कर दिया गया है। हम लोगों ने चुनाव के समय में जो 18 लाख आवास देने की बात कही थी वह हम पूरा करेंगे और इसके लिए हमारी सरकार उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मिलेंगे 10000 आवास

सीएम साय ने कहा- नियत नेल्फ़नार योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित जिलों में कई विकास योजनाओं की शुरुआत हमारी सरकार कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमने निवेदन किया था उनके लिए अलग से आवास दिया जाए। जिस पर उन्होंने उचित विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की जानकारी मिली है कि इस योजना और नक्सल क्षेत्रों के गांवों के लिए लगभग 10000 आवास योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है। उनके लिए भी हम आवास बनाने में सफल होंगे।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा-

धान के रख-रखाव और उठाव में लापरवाही से हुआ एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान

■ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पलटवार

रायपुर। नेता-प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन 2023 में की गई रिकॉर्ड धान खरीदी के रख-रखाव और उठाव में सरकार की लापरवाही से 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने की बात कही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढना चाहिए, जो काम कर सके।

नेता-प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत ने आज राजीव भवन में प्रेसवार्ता में जिलेवार आंकड़े जारी कर कहा कि 2023 में रिकॉर्ड 1 लाख 44 हजार से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा धान की इस मात्रा के भंडारण, मीलिंग तथा

चावल के उपार्जन एवं भंडारण की कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केन्द्रों से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान और संग्रहण केन्द्रों से 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि खरीदी केन्द्रों में शेष नजर आ रहा 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इस धान की कुल लागत 166 करोड़ 56 लाख रुपए होती है। इसी तरह से संग्रहण केन्द्रों में शेष धान 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल की कुल लागत 870 करोड़ 99 लाख रुपए होती है, इसमें से भी अधिकांश धान पानी से डैमेज हो चुका है, इसलिए कस्टम मीलिंग के लिए राईस मिलर्स इसका उठाव नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर 1 हजार 37 करोड़ 55 लाख रुपए का धान खराब हुआ है।

उप मुख्यमंत्री ने कसा तंज

नेताप्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत के आरोप को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निराधार करार देते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढना चाहिए, जो काम कर सके। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय की सरकार का साल नहीं बीता है, और एक-एक चीज पूरा करने वाली है। आवास का एक विषय जो रह गया था, वह आज पूरा हो गया है।

झारखंड के चुनावी दौरे पर केदार , सिमडेगा में सैकड़ों लोगों को कराया भाजपा में प्रवेश

रायपुर/ जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के वन, सहकारिता एवं संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। राज्य के सिमडेगा में केदार कश्यप की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी के लोककल्याणकारी कार्यों व योजनाओं से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने भाजपा प्रवेश किया।

सिमडेगा के प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर केदार कश्यप ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सिमडेगा में आमजनों के भाजपा में प्रवेश को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा में राष्ट्रवाद और जनकल्याण पर आधारित है। यह पार्टी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर उन्होंने कहा, भाजपा ने देश में कई बड़े चुनाव जीते हैं, और केंद्र और राज्यों में सरकार में रही है। यह पार्टी देश के विकास और प्रगति के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक ले जाना होगा। इसी तरह हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखना होगा।

इस मौके पर केदार कश्यप ने कहा कि राज्य में पांच साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुशासन से प्रदेश की जनता आहत है। यहां सिर्फ एक परिवार के हित साधने का काम हुआ है। भ्रष्टाचार से तंग प्रदेश की जनता अब भाजपा की ओर भरोसे और उम्मीद से देख रही है।

जोरों-शोरों से चल रही है गणेशोत्सव की तैयारी

रायपुर। राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव की तैयारी राजधानी में जोरों-शोरों पर चल रही हैं। तीन दिनों पहले से ही शहर में गणेश आगमन की शुरुआत हो चुकी है। गणेश स्थल सजावट के किए पंडाल सजाए जा रहे हैं। वहीं इस बार विद्युत सजावट भी देखने लायक रहेगी।

मूर्तिकार भी इस बार भारी-भरकम गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। वहीं इन सबसे हटकर रायपुरा का यादव परिवार इको फ्रेंडली श्री गणेश की मिट्टी रहित मूर्तियां बना रहा है। इसकी जानकारी देते हुए मूर्तिकार राहुल यादव ने बताया कि पिछले कई वर्षों से राहुल अपने पिता शिवचरण और बहन राशि यादव के साथ में अपने पिता और बहन के साथ में गणेश बनाने का काम कर रहे है।

उन्होंने बताया की इस बार कटर, पेंसिल, मोर पंख, चॉकलेट एवं कैंडल से भी श्री गणेश की मूर्तियां बन रही हैं। नारियल जूट से शंकर भगवान, छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में छतीसगढ़ के राजा श्री गणेश की मूर्ति भी बना रहे हैं।

राहुल ने बताया की रायपुरा में मूर्तियां बना रहे हैं। राहुल की माता भी हाथ बंटाती है। पिता शिवचरण लगभग 15 वर्षों से यूनिक और इको फ्रेंडली मूर्ति बना रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। जिससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है।

1500 से 50 हजार तक की मूर्तियों का निर्माण इस साल हो रहा है, जो इस बार लोगों को गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न सार्वजनिक पंडालों में देखने को मिलेंगे। इनकी मूर्तियों में मिट्टी का थोड़ा भी उपयोग नहीं होता, बल्कि कागज से बेस तैयार करके उस पर यूनिक आइटम डाल कर मूर्तियां बनाई जा रही है। आज के समय जब प्रदूषण हर जगह है, ऐसे में इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाना सराहनीय है। अब उनके पास रायपुर के अलावा दूसरे शहरों से भी मूर्तियों की मांग आने लगी है।

गणेश पंडाल स्थल पर सीसीटीवी से होगी निगरानी, स्वछता का रखें ध्यान

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर कलेक्टोरट स्थित रेडक्रास सभागार में गणेश उत्सव समितियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें एडीएम श्री देवेंद्र पटेल सभी को एनजीटी के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी से शांतिभंग नहीं करने की भी अपील की। बैठक के दौरान गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से यातायात बाधित न हो इसके लिए सडक किनारे पंडाल नहीं लगाने की बात कही। गणेश उत्सव के आयोजन को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, स्थानीय प्रशासन और गणेश उत्सव समितियों के प्रतिनिधियों ने एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया।

बैठक में एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिमाओं की विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। साथ ही सभी पंडालो पर सुरक्षा के लिहाज से पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वांलटियर रखने की बात कही। इसके अलावा समिति के सदस्यों को बताया गया कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए। पॉलिथीन थैलियों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

जिन्होंने सत्ता से लेकर संगठन तक भ्रष्टाचार किया हो उनके मुँह से भ्रष्टाचार की बातें अच्छी नहीं लगती: शर्मा

भाजपा सरकार में किसानों का समुचित रूप से सर्वतोमुखी विकास हो रहा है

रायपुर। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा धान खरीदी, उसकी कस्टम मिलिंग व उसके रखरखाव में भ्रष्टाचार के आरोप पर कड़ा ऐतराज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय पर कांग्रेस का कुछ भी बोलना सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली के चरित्र का परिचायक है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सुशासन वाली सरकार ने किसानों के कल्याण, उनके आर्थिक सशक्तीकरण और कृषि को लाभकारी बनाने के जितने काम पारदर्शिता के साथ किए हैं, कांग्रेस के लोग उसे पचा नहीं पा रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि सत्ता में रहकर हर मौकों को अपने लिए भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अवसर बनाने के माहिर खिलाड़ी कांग्रेस के लोगों को अब भी वही सब उसी तरह नजर आ रहा है जैसे पीलिया के मरीज को सब कुछ पीला-पीला नजर आता है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के नाम पर ढोल पीट-पीटकर कांग्रेस की सरकार ने कदम-कदम पर किसानों के साथ न केवल छल-कपट की पराकाष्ठा की, अपितु धान खरीदी के नाम पर उनके स्वाभिमान व सज्जनता को रौंदने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को चार किश्तों में उनकी उपज का मूल्य तड़पा-तड़पाकर गांधी परिवार के लोगों

के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर खैरात की तरह दिया जाता था। श्री शर्मा ने महंत समेत तमाम कांग्रेस नेताओं को याद दिलाया कि 2 साल का बकाया बोनस देने का वादा करके कांग्रेस अपने उस वादे से मुकर गई थी। अनलिमिटेड धान की खरीदी करेंगे, यह वादा राहुल गांधी ने किया था, वह भी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने आते ही किसानों को उनकी उपज का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त दिया, धान खरीदी की लिमिट को प्रति एकड़ 21 क्विंटल कर दिया और साथ ही 2 वर्षों के बकाया बोनस का भी भुगतान कर दिया। केंद्र सरकार ने भी किसानों के हित के लिए नई-नई योजनाओं को लागू किया है, उनकी स्वीकृति भी कैबिनेट में दी है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। किसानों का समुचित रूप से सर्वांगीण विकास हो रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि दरअसल कांग्रेस इसी बात से पूरी तरह से निराश व हताश है और गाहे-बगाहे अनर्गल बातें करके बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस की अब यही नियति हो गई है। उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा है।

शर्मा ने कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार का विषय है, महंत समेत कांग्रेस नेताओं को पहले अपनी पार्टी और पिछली भूपेश सरकार के कार्यकाल में झाँककर देखना चाहिए जहाँ सत्ता से लेकर संगठन तक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है! आज उसी कांग्रेस पार्टी में टिकट की खरीदी-बिक्री के आरोप तक लग रहे हैं। अरुण सिसौदिया ने कांग्रेस संगठन के फंड में भूपेश बघेल के करीबियों द्वारा घोटाला करने की शिकायत की है। श्री शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भूपेश सरकार के कई दिग्गज अधिकारी अभी जेल में है। जिन्होंने सत्ता से लेकर संगठन तक भ्रष्टाचार किया हो, उनके मुँह से भ्रष्टाचार की बातें अच्छी नहीं लगती। श्री शर्मा ने नसीहत दी कि नेता प्रतिपक्ष महंत बड़े नेता हैं। उनको चाहिए कि कांग्रेस ने जो किया है, उस पर अपनी राय रखें और कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है, उसके बारे में जनता को बताएँ।

सरकारी अस्पताल में शुरू होगा लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा: जायसवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ जल्द ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने वाला राज्य बनने जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जानकारी साझा करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी। अस्पताल में पहले से ही अत्याधुनिक आईसीयू तैयार किया जा चुका है और ट्रांसप्लांट के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के 6 जिलों में अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन अस्पतालों से न केवल राजधानी के मरीजों, बल्कि आस-पास के राज्यों के मरीजों को

भी लाभ मिलेगा।

मंत्री जायसवाल के अनुसार, अंबेडकर अस्पताल में आईवीएफ सेंटर स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए रुकी हुई डीपीआर का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अंबेडकर अस्पताल में एक आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस भी बनाया जाएगा, जिसमें नवीनतम उपकरण और विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए नई वर्चुअल मशीन की स्थापना की जा रही है। यह मशीन देश की सबसे आधुनिक तकनीक से युक्त होगी, जिससे पोस्टमार्टम के कार्यों में तेजी आएगी और राजधानी के लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में नई सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें दूरस्थ परामर्श, अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग, और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता शामिल होगी। इससे राज्य के सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

फार्मेसी काउंसिल के आनलाइन पंजीयन सुविधा का किया लोकार्पण

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पंजीयन की आनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया है। अब फार्मेसी काउंसिल का पंजीयन सिस्टम आनलाइन हो गया है। इससे फार्मेसी छात्र तथा फार्मासिस्टों को पंजीयन अथवा नवीनीकरण के लिए रायपुर स्थित फार्मेसी काउंसिल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब पंजीयन कराने के लिए आनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को केवल एक बार दस्तावेजों के वेरीफिकेशन के लिए काउंसिल कार्यालय आना होगा।

कार्यक्रम का लोकार्पण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पंजीयन कार्य के आनलाइन हो जाने से आवेदकों को अब काउंसिल के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जिससे उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट डाक्टर और मरीज के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिस पर सही दवा एवं खुराक के निर्धारण की जिम्मेदारी होती है।

अभी तक फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन के लिए राज्य के सभी जिलों के विभिन्न स्थानों के फार्मेसी उत्तीर्ण छात्र फार्मासिस्ट पंजीयन के लिए रायपुर स्थित काउंसिल कार्यालय आते थे। इसी प्रकार पंजीकृत फार्मासिस्टों को नवीनीकरण के लिए रायपुर आना पड़ता था। अब पंजीयन तथा नवीनीकरण की व्यवस्था आनलाइन हो जाने से राज्य के सभी फार्मेसी छात्र एवं पंजीकृत फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 33 हजार 300 फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं। ये फार्मासिस्ट रिटेल दवा दुकान, थोक दवा दुकान, दवा निर्माण इकाइयों जैसे कार्यों को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

यूएई, मिस्त्र, ओमान के बाद ब्रुनेई से मोदी का दुआ सलाम

अभिनय आकाश

पीएम मोदी ऐसे देश पहुंचे जहां 82 प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है। हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा रहा। अपने ब्रुनेई दौरे में नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रुनेई के संबंधों को और मजबूत करने का तो काम किया ही और एक काम ऐसा भी किया जिसे हिंदुस्तान के एक तबके को जरूर देखना चाहिए जो पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। पीएम मोदी के हर फैसले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। भड़काऊ बातें करते हैं। पीएम मोदी ने ब्रुनेई में वहां से सबसे पुराने और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रसिद्ध उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। इसका नाम ब्रुनेई के 28वें सुल्तान के नाम पर रखा गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी किसी मस्जिद में गए हों। इससे पहले भी पीएम मोदी यूएई के शेख जायद मस्जिद, ओमान के सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद, सिंगापुर के चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया के इस्तिकलाल मस्जिद और मिस्त्र के अल-हकीम बी-अम्र अल्लाह मस्जिद भी जा चुके हैं। भारतीय उच्चायोग की नई चांसरी के उद्घाटन के तुरंत बाद पीएम मोदी ने क्षेत्र की सबसे प्रमुख मस्जिदों में से एक का दौरा किया। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद ब्रुनेई के 28वें सुल्तान के नाम पर है, जिन्हें आधुनिक ब्रुनेई का वास्तुकार और वर्तमान सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के पिता माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत ब्रुनेई के धार्मिक मामलों के मंत्री पेहिन दातो उस्ताज़ हाजी अवांग बदरुद्दीन ने किया। ब्रुनेई के स्वास्थ्य मंत्री दातो डॉ. हाजी मोहम्मद ईशाम भी उपस्थित थे। जून 2023 में राजधानी काहिरा में भारतीय नेता 11वीं सदी की अल-हकीम मस्जिद का दौरा किया था। इस मस्जिद का नाम छठे फातिमिद खलीफा अल-हकीम द्वि-अम्र अल्लाह के नाम पर रखा गया है। मस्जिद काहिरा में दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। देश की चौथी सबसे पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद का मिस्र सरकार द्वारा बोहरा समुदाय के सहयोग से नवीनीकरण किया गया था। यह संरचना 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें प्रतिष्ठित केंद्रीय प्रांगण 5,000 वर्ग मीटर में फैला है। अपनी मई 2018 की इंडोनेशिया यात्रा के हिस्से के रूप में, मोदी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भव्य इस्तिकलाल मस्जिद का दौरा किया। इस्तिकलाल स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अरबी शब्द है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और क्षमता के मामले में तीसरी सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद है। 1978 में जनता के लिए खोली गई मस्जिद में 120,000 से अधिक उपासक रह सकते हैं। मर्डेका स्क्वायर और जकार्ता कैथेड्रल के बगल में स्थित इस संरचना को बनने में 17 साल लगे। मस्जिद का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और सऊदी अरब के राजा सलमान शामिल हैं। जून 2018 में अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान मोदी ने चुलिया मस्जिद और श्री मरिअम्मन मंदिर का दौरा किया। मध्य क्षेत्र के चाइनाटाउन जिले में साउथ ब्रिज रोड पर स्थित, यह सिंगापुर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसकी स्थापना 1826 में चुलियास द्वारा की गई थी, जो भारत के कोरोमंडल तट के तमिल मुस्लिम व्यापारी थे। फरवरी 2018 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले, पीएम मोदी ने मस्कट में सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद, जो गैर-मुस्लिम आगंतुकों को अनुमति देती है, शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। उनके साथ ओमान के पूर्व राजा, सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद और अन्य अधिकारी भी थे। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और मस्जिद में समर्थकों से मुलाकात की। अगस्त 2015 में प्रधान मंत्री मोदी ने निवेश और आतंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान ही यूएई नेतृत्व ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा था, अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायहान अपने पांच भाइयों के साथ हवाईअड्डे पर एक दुर्लभ भाव से उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। ब्रुनेई के सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पीएम मोदी ऐसे समय में गए जब हिंदुस्तान के भीतर बिल्कुल अलग है। बात जातियों और धर्म की ज्यादा हो रही है। पीएम मोदी के हर फैसले पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। वक्फ बोर्ड पर फैसला हो या फिर बात यूसीसी की हो। हिंदुस्तान में एंटी मोदी ब्रिगेड लगातार पीएम मोदी को टारगेट कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ब्रनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में मौजूद होकर हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया को भी बड़ा संदेश दिया।

सर्वसुलभ इंसाफ की उम्मीद को पंख लगे

ललित गर्ग

यह सुखद, अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक अवसर ही है कि देश के सर्वच्च न्यायालय ने 75 साल का गरिमामय सफर पूरा कर लिया है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को यादगार बनाने के लिये बाकायदा डाक टिकट व सिक्के भी हाल ही में जारी किये गए और विभिन्न आयोजनों में सर्वच्च न्यायालय की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने के विषय पर गंभीर मंथन भी हुआ, ऐसे ही आयोजनों में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड ने इस बात पर बल दिया कि समय पर न्याय मिलने से ही न्याय का वास्तविक लक्ष्य पूरा होता है। 'न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है' वाली इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की इस स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।'

सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती के अवसर पर सभी ने शीघ्र न्याय की जरूरत को स्वीकारते हुए कहा कि 'तारीख पे तारीख' की संस्कृति से तौबा करने का वक्त आ गया है? न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने ही चाहिए। यही वजह है कि जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कुछ कहा, उसे देश की पूरी न्याय व्यवस्था के लिए अलार्म बेल माना जा सकता है। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि जब तक न्यायपालिका देश के आम लोगों को सहजता से इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता मुहैया नहीं कराती, तब तक उसका काम पूरा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्वीकारा कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिये बड़ी चुनौती है।

अदालतों से न्याय पाने की प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है और इसमें बेहिसाब वक्त लगता है। इन दोनों ही का नतीजा इसी रूप में सामने आता है कि इंसाफ की आस लेकर अदालत पहुंचा व्यक्ति फैसला आने तक टूट चुका होता है। इसीलिये राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि किसी गंभीर अपराध से जुड़े मामले का फैसला आने में 32 साल लग जाए तो लोगों को ऐसा लगना अस्वाभाविक नहीं कि शायद अदालतें ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। राष्ट्रपति ने किसी खास मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा अजमेर में पॉक्सो अदालत द्वारा इसी 20 अगस्त को सुनाए गए फैसले की तरफ था। एक चर्चित सेक्स स्कैंडल से जुड़े इस मामले में छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने में 32 साल लग गए। यह अपनी तरह का कोई इकलौता मामला नहीं है। बेहद गंभीर और वीभत्स अपराध के सैकड़ों ऐसे मामले हैं, जो अदालतों में बरसों से लंबित पड़े हैं। लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश-निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य न हों? प्रश्न यह भी है उन्हें समय पर त्वरित न्याय कब मिल सकेगा? दुर्भाग्य से ये प्रश्न दशकों से अनुत्तरित है।

इससे पहले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ सके। निस्संदेह, हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे समाजशास्त्री और कानून लागू करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां भी हैरान-परेशान हैं। कोलकाता में एक मेडिकल कालेज के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या कांड ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। पूरे देश में अपराधियों को शीघ्र व सख्त दंड देने की मांग की जा रही है। यदि पुलिस व जांच एजेंसियां पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पहुंचें तो गंभीर मामलों में आरोप जल्दी सिद्ध हो सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का। नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तम्भ है। भारत में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों को मज़बूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान का रखवाला, ग़रीबों के अधिकार एवं सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ़ कमज़ोर समूहों का योग्य संरक्षक और करोड़ों नागरिकों के लिए आखरी उम्मीद वाला संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले 75 वर्षों में ज्यादातर समय भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा और क़ानून के शासन को बनाए रखने में सफल रही है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था के सामने अनेक जटिल स्थितियां भी हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, बढ़ते केसों की संख्या, जवाबदेही, भ्रष्टाचार एवं विलम्बित न्याय आदि। न्याय को लेकर अदालतों तक आम नागरिकों की पहुंच एवं खर्च के मुद्दों और इसी तरह की दूसरी चीज़ों के मामले में सुधार के बारे में न्यायपालिका की अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। हमारे कानूनों की भावना है-नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले है।

निश्चित ही डी.वाई. चंद्रचूड न्याय-प्रक्रिया की कमियों एवं मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं तो उनमें सुधार के लिये जागरूक दिखाई दिये हैं। निश्चित ही उनसे न्यायपालिका में छाये अंधेरे सायों में सुधार रूपी उम्मीद की किरणें दिखाई देती रही है। न्याय के इंतजार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज एवं चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80 हजार है। उच्च न्यायालयों में इनकी संख्या 62 लाख के करीब है और निचली अदालतों में करीब साढ़े चार करोड़। इसका अर्थ है कि लगभग पांच करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। देश में तीनों स्तरों पर लंबित मामले न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है। आजादी के अमृत महोत्सव की चौखट पार कर चुके देश की इस त्रासद न्याय व्यवस्था के बाबत देश के नीति-नियंताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित ही भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों व न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है।

निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि और अधिकतम तारीखों की संख्या तय होनी ही चाहिए। जैसाकि अमेरिका में किसी भी मामले के लिये तीन वर्ष की अवधि निश्चित है। लेकिन भारत में मामले 20-30 साल चलना साधारण बात है। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना में भी सुधार जरूरी है। उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशों की तरह भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका है। तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके इसके लिये हाल ही में लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। नये तीन कानूनों के बाद मुकदमों की सुनवाई द्रुत गति से होगी, लेकिन देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं? प्रश्न यह भी है कि आखिर करोड़ों लंबित मामलों का क्या होगा? ये वे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर देश की जनता को चाहिए। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-13)

गतांक से आगे...

हाँ! यदि तन्त्र भी वेदानुकूल हो तो उसे निस्सन्देह प्रमाण भानना चाहिए परन्तु प्रत्यक्ष श्रुति के विरुद्ध किसी भी अंश को कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्योंकि केवल वेद ही धर्म- निर्णय में सर्वथा प्रमाण है अत: जो भी तदनुकूल हो सो प्रमाण है और जो तदूविरुद्ध हो सो अप्रमाण है।

(मीमांसा-प्रक्रिया)- धर्म-निर्णय के सर्वोत्तम ग्रन्थ, मीमांसा-शास्त्र में उक्त प्रामाण्या- प्रामाण्य के विषय में एक विशेषता प्रकट की है। वह यह कि यदि स्मृति पुराण आदि ग्रन्थों का कोई वाक्य प्रत्यक्ष श्रुति के विरुद्ध दीख पड़े तथ तो वह उपेक्षणीय है परन्तु प्रत्यक्ष श्रुतिति में यदि किसी स्मृति आदि वाक्य के अनुकूल या विरुद्ध दोनों प्रकार का ही उल्लेख न मिले तो उस वाक्य को अनुमित श्रुति-मूलक मानकर प्रमाण कोटि में समझना चाहिये । यथा- विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्।। अर्थात्-स्मृत्यादि ग्रन्थों का प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध अंश प्रमाण नहीं हो सकता परन्तु वेद में (असति) जिस वाक्य के विरुद्ध या अनुकूल कोई वचन उपलब्ध न हो तो वहाँ परोक्ष श्रुति का अनुमान करके उसे वेदमूलक एवं प्रमाण मानना चाहिये।

न्याय-प्रक्रिया- न्बायदर्शन के टीकाकार महर्षि वात्स्यायन ने समारोपणा-दात्मन्यप्रतिषेध: (4।1।62) सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि- वेद, स्मृति और पुराण विषय-व्यवस्था के अनुसार अपने अपने विषय में इन्द्रियों की भान्ति निरपेक्ष प्रमाण हैं।

वेद का एक भिन्न विषय है, और इतिहास पुराण तथा धर्मशास्त्र का अलग 2 विषय है। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद का विषय है यज्ञ । इतिहास पुराण का विषय है लोकबीती। और धर्मशास्त्र का विषय है लोक व्यवहार की स्थापना।

क्रमश: ...

शिक्षक दिवस

डॉ. पवन सिंह मलिक

भारत के राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दार्शनिक चिन्तन, जीवन मूल्यों को लोकजीवन में संचारित करने की दृष्टि एवं गिरते सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का संकल्प कालजयी है जो युगों-युगों तक राष्ट्र एवं समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा, उनका जन्म दिवस 5 सितम्बर पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे एक ऐसे ही प्रकाश-स्तंभ हैं, जिन्होंने अपनी बौद्धिकता, सूझबूझ, व्यापक सोच से भारतीय संस्कृति के संक्रमण दौर में संबल प्रदान किया। वे भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान् शिक्षाविद, महान् दार्शनिक, महा-मनीषी अध्येता, समाज-सुधारक, राजनीतिक चिन्तक एवं भारत गणराज्य के राष्ट्रपति थे। वे समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है और यही आदर्श समाज संरचना का आधार है।

दुनिया सुनना नहीं, देखना पसंद करती है कि आप क्या कर सकते हैं.... और अपने अंदर छिपी इसी असीम शक्ति की पहचान करवाना, मैं कौन हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ इस भाव को परिणाम में बदलने के लिए प्रेरित करने की प्रेरणा है शिक्षक। आज शिक्षक दिवस है और हममें से कोई भी ऐसा नहीं, जिसके जीवन में इस शब्द का महत्व न हो। हम आज जो कुछ भी हैं या हमने जो कुछ भी सीखा या जाना है उसके पीछे किसी न किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग व उसे सिखाने की भूमिका रही है। इसलिए आज का दिन प्रत्येक उस व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का व उन सीखे हुए मूल्यों के आधार पर खुशहाल समाज निर्माण में अपनी भूमिका तय करने का दिन भी है। शिक्षक यानि गुरु शब्द का तो अर्थ ही अंधकार (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले जाने वाला है। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का श्री गणेश भी हो चुका है। पूरी शिक्षा नीति को देखने पर ध्यान आता है कि उसके क्रियान्वयन व सफ़ल तरीके से उसे मूर्त रूप देने का अगर सीधा-सीधा किसी का नैतिक दायित्व बनता है तो वह शिक्षकों का ही है। वर्तमान के आधार को मजबूत करते हुए, भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को चरितार्थ करने व भारत को आगे बढ़ाने के सपनों को अपनी आँखों में भर कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा व भाव जागरण का आधार भी शिक्षक है। जिंदगी में उत्साह व भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरी हुई पीढ़ियों का निरंतर निर्माण करते रहना, यही शिक्षकत्व की पहचान है और यही शिक्षक दिवस की सार्थकता भी।

शिक्षक जो जीवन के व्यावहारिक विषयों को बोल कर नहीं बल्कि स्वयं के उदाहरण से वैसा करके सिखाता है। शिक्षक जो बनना नहीं गढ़ना सिखाता है। शिक्षक जो केवल शिक्षा नहीं बल्कि विद्या सिखाता है। शिक्षक केवल सफ़ल होना नहीं, असफ़लता से भी रास्ता निकाल लेना सिखाता है। शिक्षक जो तर्क व कुतर्क के अंतर को समझाता है। शिक्षक जो केवल चलना नहीं, गिरकर उठना भी सिखाता है। शिक्षक जो भविष्य की चुनौतीयों के लिए तैयार होना सिखाता है।

हिंसा की आग में झुलसता बलूचिस्तान

राजेश बादल

किसी भी मुल्क के सूबे के लिए यह विकट स्थिति होती है कि वह अपने को देश का हिस्सा ही नहीं माने और वह राष्ट्र भी उसे अपनाए नहीं। दोनों पक्षों के मन में बेगानेपन का भाव है। फिर भी वे साथ रहने के लिए मजबूर हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान ऐसा ही इलाका है। बीते 77 बरस में न उसने पाकिस्तान को अपनाया और न ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को। वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए छटपटा रहा है और पाकिस्तान की फौज वहां की जन भावनाओं को बूटों तले रौंद रही है।

बलूचिस्तान का हालिया घटनाक्रम बड़े क्रूर और हिंसक दौर का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान को नहीं मिला था। पाकिस्तान ने विभाजन के बाद उसे जबरन हड़पा था। वह भी धोखा देकर। दरअसल स्वतंत्र देश बलूचिस्तान के साथ अंग्रेजों की रक्षा, विदेश नीति और व्यापार की संधि थी। जब गोरे गए तो यह संधि खत्म हो गई और बलूचिस्तान फिर दस अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश के रूप में आ गया। लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नवाब बुगती को धोखा देकर वही संधि पाकिस्तान से करा ली, जो बरतानवी लोगों के साथ थी। इसके बाद धीरे-धीरे उसने समूचा बलूचिस्तान ही हड़प लिया। पाकिस्तान की इस हरकत के विरोध में वहां के सबसे बड़े सियासी बुगती परिवार की अगुआई में बलोच आजादी का आंदोलन चलाते रहे हैं।

संदर्भ के तौर पर बता दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बलोचों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय थीं। जब बांग्लादेश बना तो बलोचों की आशाएं भारत से जगी थीं। पाकिस्तान बांग्लादेश के अलग

होने के दर्द से दुखी था तो बलूचिस्तान में खुशियां मनाई जा रही थीं। वहां के नागरिक सड़कों पर इंदिरा गांधी और जनरल मानेक शॉ के पोस्टर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैलियां निकाल रहे थे। वे चाहते थे कि भारत बांग्लादेश की तरह हस्तक्षेप करे और उन्हें पाकिस्तान से आजादी दिलाए। इसके बाद बलोची संघर्ष करते रहे और पाकिस्तान उन्हें सूली पर चढ़ाता रहा।

जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में तो बुगती खानदान के सबसे बड़े नेता नवाब अकबर बुगती को सेना ने मार डाला था। सेना ने अपने ही प्रदेश पर रॉकेटों से हमला किया था। तब से बलूचिस्तान आजादी के लिए उबल रहा है। अलगाववादी पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। वे अपने साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे हक मांगते हैं तो उन्हें गोलियां मिलती हैं। गुजिश्ता 77 साल का अतीत इस बात का गवाह है। बलूची लोग हजारों माटी पुत्रों की बलि चढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान की थल सेना ने उन पर टैंकों से हमला किया है। वायुसेना ने उन पर बम बरसाए हैं और ठीक वैसी ही जंग छेड़ी है जैसी इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच जारी है।

पिछले एक महीने में बलूचिस्तान में जारी हिंसा में सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मारे गए लोगों में से पंजाब सूबे के रहने वाले और सुरक्षाकर्मी हैं। एक स्वयंसेवी संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते 25 साल में 25 हजार से अधिक बलूची लापता हो गए। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपने यातनागृहों में मार डाला है।

लेकिन मौजूदा हिंसा के पीछे चीन भी एक बड़ा कारण है। उसने ग्वादर में बंदरगाह बनाया है। पाकिस्तान ने यह बंदरगाह उसे लीज पर दे दिया है। चूंकि बलूचिस्तान भौगोलिक आधार पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां खनिज संसाधनों से लेकर गैस तक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए चीन वहां तक अपने गलियारे (सीपीईसी) का निर्माण कर रहा है।

बलूचिस्तान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बलूची लोग इसलिए चीन से खफा हैं। दो दशक में चीन के कई इंजीनियर वहां मारे जा चुके हैं। चीनी मजदूरों ने भी जान गंवाई है। इससे चीन पाकिस्तान से नाराज है। उधर, पाकिस्तान जब तब आरोप लगाता रहता है कि बलूचिस्तान में अशांति और हिंसा के पीछे भारत का हाथ है। वह सोचता है कि बांग्लादेश की तरह भारत बलूचिस्तान को भी उससे अलग करा देगा। लेकिन पाकिस्तान यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि बलूचिस्तान में हिंसा के बीज उसके भीतर ही छिपे हुए हैं। वह तो मुल्क के बाशिंदों की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। यह सवाल अब वहां के आम नागरिकों को परेशान कर रहा है कि बलूचिस्तान में मतदाता सुरक्षित नहीं हैं। पंजाब के लोग सुरक्षित नहीं हैं। सिंध के निवासी मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाके में लोग अपने को सुरक्षित नहीं मानते और पाक अधिकृत कश्मीर में भी लोग भयभीत हैं तो फिर इस पड़ोसी राष्ट्र में कौन सुरक्षित है?

दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भारत की निकटता के कारण भी हैं। बलूचिस्तान के लोगों का स्वाभाविक मेलजोल पाकिस्तान की तुलना में भारतीय संस्कृति के ज्यादा निकट है। उस क्षेत्र का इतिहास हिंदू जीवन शैली और बौद्ध धर्म के साथ का रहा है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आज भी बलूचिस्तान की घाटियों में बिखरे पड़े हैं। कभी यह इलाका कुषाणों के शासन का साक्षी रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का विस्तार बलूचिस्तान तक किया था और बाद में यहां से होते हुए बौद्ध धर्म का अफगानिस्तान तक गहरा असर देखा जा सकता था।

आज के अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं तक बुद्ध की शिक्षाओं के निशान पाए जाते हैं। क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि हिंदुस्तान के पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में बौद्ध धर्म के शांति संदेश फैले हुए थे। पर, आज का पाकिस्तान न अपने अतीत के दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहता है और न चीन ही अपने इतिहास के अध्याय को पढ़ना चाहता है, जब वहां बाकायदा बौद्ध राजधर्म स्थापित किया गया था।

आज का इतिहास

1839 पहला अफीम युद्ध चीन में शुरू हुआ था।
1839 व्यापार विवादों की चरमावस्था में पहुचने के कारण पूर्वी चीन में चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध की शुरुआत हुई।
1877 ओगला लाकोटा युद्ध के नेता क्रेज़ी हॉर्स कैंप रॉबिन्सन-इन-डे नेब्रास्का में कथित रूप से कैद का विरोध करते हुए आफत में घायल हो गए थे।
1882 पहला संयुक्त राज्य अमेरिका श्रम दिवस परेड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया।
1887 इंग्लैंड के थिएटर रॉयल एक्सेटर में आग लगने से 186 लोग मारे गए।
1912 स्कूटरी शहर के नजदीक हेममेली में तुर्कों द्वारा पंद्रह ईसाइयों का नरसंहार किया गया।
1914 विश्व के 5 देशों ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस ने लंदन संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
1914 प्रथम विश्व युद्ध : मार्ने की पहली लड़ाई फ्रांसीसी बलों के साथ पेरिस के पास मार्ने नदी में जर्मन सेना को आगे बढ़ाने के साथ शुरू हुई।
1920 मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव आरम्भ हुआ।
1927 वॉल्ट डिज़्नी और यूबी इवर्क्स के पहले लोकप्रिय चरित्र ओसवाल्ड लकी रैबिट ने एनिमेटेड कार्टून ट्रॉल्स ट्रबल में अपनी शुरुआत की।
1945 शीत युद्ध : सोवियत सिफर क्लर्क इगोर गोज़ेंको ने सोवियत जासूसी गतिविधियों और स्लीपर एजेंटों पर 100 से अधिक दस्तावेजों के साथ कनाडा को हराया।
1948 रॉबर्ट सुमन फ्रांस के प्रधानमंत्री बने।
1960 मुहम्मद अली के नाम से मशहूर अमेरिकी बॉक्सर कैसियस क्ले ने ओलंपिक में लाइट हेवीवेट का स्वर्ण पदक जीता।
1969 पहली स्वचालित टेलर मशीन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के रॉकविल केंद्र में स्थापित की गई।
1975 पार्क लेन में लंदन हिल्टन होटल पर इरा आतंकवादियों द्वारा बमबारी की गई है। दो लोगों के घायल होने की खबर है। बम होटल की लॉबी में लगाया गया था।

जातिवाद के दानव को बोतल में बंद कर दिया जाना चाहिए

पूनम आई. कौशिश

लगभग तीन दशक पहले राजनीतिक दलों द्वारा पैदा किया गया जाति का जिन्न पुन: अपना फन फनफनाने लगा है क्योंकि 'इंडिया' गठबंधन के दलों ने भारत की सबसे पुरानी कमजोरी जातिवाद को पुन: मुद्दा बना दिया है। हालांकि यह मुद्दा बहुत जटिल है। कई बार यह गहरे आघात करता है और कई बार यह धोखे और प्रपंच के माध्यम से जातीय मतभेद बढ़ाता है, किंतु किसे परवाह? यह मुद्दा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति के समक्ष आया। राजग के घटक दल जद (यू) और लोजपा ने इस पर चर्चा की मांग की। वस्तुत: पिछले दो वर्षों में विपक्ष शासित बिहार में जद (यू) और राजद ने जातीय सर्वेक्षण शुरू किया और अब इसका प्रभाव अन्य राज्यों ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक पर भी पडऩे लग गया है क्योंकि यह लोगों की सामाजिक राजनीतिक चेतना को जगा रहा है और यह चुनावी टैग और पहचान से आगे बढ़ रहा है तथा लोगों को जातीय आधार पर विभाजित कर रहा है, जैसा कि अडवानी की अयोध्या रथ यात्रा के दौरान मंडल-कमंडल विवाद हुआ।

'इंडिया' गठबंधन इस सोच में है कि जब जाति आजीविका के मुद्दों का केन्द्र बन जाएगी, जो पहचान और आरक्षण के केन्द्र में है, तो इससे धर्म की बजाय जातीय आधार पर अधिक चुनावी लाभ मिलेगा। कांग्रेस नेता ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले ही बिगुल बजा दिया है कि जितनी आबादी, उतना हक और उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी को गद्दी से हटाना है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना का लक्ष्य अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण है, किंतु यह वास्तव में हिन्दू मतों को जातीय आधार पर विभाजित कर 2024 के चुनावों के बाद भाजपा को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के अनुसार, जातीय जनगणना एक अन्य मुद्दे को और भाजपा के लिए समस्या पैदा कर देगी। फिर धुरी मोदी समर्थक और मोदी विरोधी बनेगी और हम अन्य पिछड़े वर्गों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, जो मंडल 2.0 होगा जो मंडल 1.0 से अलग होगा, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों का आक्रामक ध्रुवीकरण किया गया था। उनका मानना है कि जातीय जनगणना उनके मतों को कई गुना बढ़ाएगी।

लोगों में आरक्षण के बारे में भय पैदा करके लोकसभा चुनाव में भाजपा से दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को बड़ी संख्या में दूर किया गया था और इसलिए धर्म आधारित ध्रुवीकरण में भाजपा का स्थान सिमट गया था। विशेषकर इसलिए भी, कि राजग के कुछ सदस्य और घटक दल मंडल के लाभार्थी हैं और वे अपने राजनीतिक एजेंडा में जातीय जनगणना को अगला तार्किक कदम मानते हैं। मंडल राजनीति के बाद अब जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है और चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर लड़े जा रहे हैं। मतदाता निर्णायक रूप से जातीय आधार पर मतदान कर रहे हैं हालांकि यह पश्चगामी कदम है। उनका सोचना है कि ब्राह्मण और ठाकुर, जिनका वोट बैंक केवल 15 प्रतिशत है, उनका वर्चस्व क्यों रहे और राजनीतिक जागरूकता जातीय स्तर पर जाकर समाप्त हो रही है।

इसके अलावा जातीय जनगणना ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को दूर करने में भी सहायक होगी और सरकार की कल्याण योजनाओं और नीतियों को निर्धारित करने में उपयोगी होगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इन योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे और इस तरह वंचित वर्गों को एक नई पहचान मिलेगी और उनके दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। किंतु न जाने क्यों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपनी जातीय जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल रखा है क्योंकि इससे

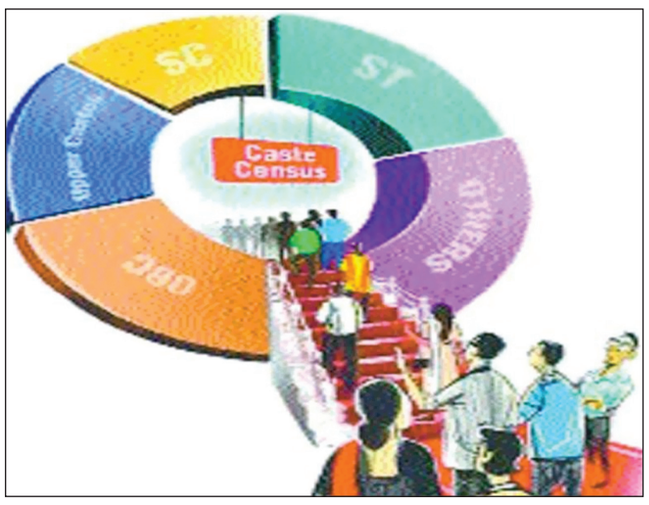

लिंगायत और वोकालिंगा के बीच विवाद पैदा हो सकता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि राज्य में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटा दिया जाए और इसे वह समय की मांग बताते हैं क्योंकि जातीय जनगणना 90 वर्ष पूर्व 1931 में की गई थी। दुखद तथ्य यह है कि वोट बैंक प्राप्त करने की चाह में किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि वे कैसा दानव पैदा कर रहे हैं।

प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जातीय जनगणना से राष्ट्रीय राजनीति और विखंडित नहीं होगी? भाजपा के लिए जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, यदि वह हाल के चुनावों में हिन्दू वोट बैंक को बचाए रखने में सफल होती और उसे 542 सदस्यीय लोकसभा में 240 सीटें नहीं मिलतीं। यही नहीं, उसे उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे केवल 33 सीटें मिलीं, जबकि 2019 में 62 सीटें मिली थीं। घाव पर नमक छिड़कने का कार्य अयोध्या में जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार ने किया, जहां पर कुर्मी, दलित और मौर्य का 8 प्रतिशत वोट बैंक है। भाजपा ने अभी तक इस बारे में कोई रुख नहीं अपनाया क्योंकि यह उसके हिन्दुत्व अभियान के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है और उसका वोट बैंक बिखर सकता है। हालांकि वह विभिन्न जातियों को हिन्दुत्व के अधीन एकजुट करना चाहती है। जातीय जनगणना करने का राजनीतिक जोखिम भी हो सकता है।

अन्य पिछड़े वर्गों को जनगणना में शामिल करने से उनकी संख्या के बारे में एक ठोस आंकड़ा मिलेगा और इससे राज्य के संस्थानों, विशेषकर न्यायपालिका, शिक्षा आदि में अन्य पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी की जांच करने में सहायता मिलेगी, जिन पर अब तक समाज के उच्च वर्गों का एकाधिकार था और दलित तथा बहुजन समाज की उनमें छोटी सी उपस्थिति है। इससे इन समूहों के लिए आरक्षण की मांग बढ़ सकती है और विद्यमान सतत् समीकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व गड़बड़ा सकता है। परिणामस्वरूप सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में एक राजनीतिक चेतना विकसित होगी और सामाजिक न्याय के लिए एक नया आंदोलन शुरू हो सकता है, जो भाजपा को हाशिए पर ले जा सकता है। भाजपा विपक्ष के 'जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी' के नैरेटिव का प्रत्युत्तर देने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कर सकती है, ताकि वह पिछड़े वर्गों में कमजोर जातियों का समर्थन प्राप्त कर सके। किंतु इस रणनीति में भी जोखिम है।

इस बार भाजपा को जातीय समूहों को हिन्दुत्व और सुदृढ़ राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट करने के फार्मूले को छोडऩा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हाल ही में किसी तरह की जातीय जनगणना के बारे में सजग किया है क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और यह केवल चुनावी लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जातीय जनगणना के लिए मांग बढ़ती जा रही है और भाजपा के पास भी अवसर है कि वह इसे अपने राष्ट्रीय एकीकरण के आह्वान के विरुद्ध विभाजनकारी एजैंडा के रूप में प्रस्तुत करे। भाजपा का राष्ट्रीय एकीकरण आह्वान हिन्दुत्व पर केन्द्रित है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने घोषणा की है कि सनातन धर्म ही जातीय जनगणना का एकमात्र प्रत्युत्तर है, चाहे इससे कोई पंडोरा बॉक्स ही क्यों न खुल जाए।

जाति समर्थकों के विचारकों का कहना है कि जाति एक सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता है और इसके बारे में ठोस आंकड़े होने से सही नीतियां बनाई जा सकती हैं। किंतु जातीय जनगणना से विभाजन, सामाजिक मतभेद बढ़ेगा, जातीय भावनाओं को बल मिलेगा, पहचान की राजनीति मजबूत होगी और जातीय आधार पर देश का विभाजन होगा। एक प्रगतिशील समाज के रूप में जातीय जनगणना आधुनिकता के प्रयोजन को विफल कर देगी। आज के आधुनिक जीवन में जाति का महत्व नहीं रह गया है किंतु यह भारत के सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय एकता को स्थायी रूप से खंडित कर सकती है। निस्संदेह जातिवाद के दानव को बोतल में बंद कर दिया जाना चाहिए। यह अविवेकपूर्ण सामाजिक समूहों की राजनीति का समय नहीं है क्योंकि इससे लोग जातीय आधार पर और बंटेंगे तथा अमीरों और गरीबों के बीच खाई और बढ़ेगी। यदि भारत को सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढऩा है तो उसे ऐसी तुच्छ राजनीति से बचना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर: किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट

उमेश चतुर्वेदी

जम्मू-कश्मीर भले ही अभी केंद्र-शासित प्रदेश हो, पर वहां के विधानसभा चुनाव पर देश ही नहीं, दुनिया की निगाह भी है। इसकी वजह है, संविधान का बहुचर्चित अनुच्छेद 370, जो अब अतीत बन चुका है। पर स्थानीय दल अब भी इसकी याद बनाये रखना चाहते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने तो इस अनुच्छेद को बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा तो नहीं किया है, पर उसकी पार्टी लाइन इस अनुच्छेद को बनाये रखने की रही है। नेशनल कांफ्रेंस भी इस अनुच्छेद की बहाली की बात करती रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं की वजह से चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा बलों के सहयोग से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और भयरहित चुनाव कराने की ठान ली है। तारीखों का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने वादा किया था कि धरती के स्वर्ग में चुनाव खुशनुमा माहौल में ही होंगे। जिस कश्मीर घाटी में आतंकवाद के उभार के बाद से बमुश्किल नौ प्रतिशत तक मतदान होता रहा है, हालिया लोकसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बारामूला, मध्य कश्मीर में श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतों के पास अनंतनाग-राजौरी में बड़ी तादाद में वोट डाले गये। चूंकि विधानसभा चुनाव कहीं ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर भी होंगे, इसलिए मतदाताओं की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर की मौजूदा विधानसभा में अब 114 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए सुरक्षित हैं। चुनाव बाकी 90 सीटों के लिए हो रहा है। इस चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि पीडीपी अकेले लड़ने की तैयारी में है। भाजपा भी अकेले मैदान में उतर रही है। उसका प्रभाव ज्यादातर जम्मू इलाके में है, जहां 43 सीटें हैं। वैसे पार्टी कश्मीर घाटी की 47 सीटों में से अधिकतर पर उतरने की तैयारी में है। चूंकि 370 हटाये जाने के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए यह चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल है। शायद यही वजह है कि पार्टी ने अतीत में राज्य में सहयोगी दलों के साथ कमल खिला चुके राम माधव को प्रभारी बनाया है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पार्टी की लोकप्रियता विशेषकर जम्मू क्षेत्र में अपने चरम पर थी। इसी इलाके के लोगों ने प्रजा मंडल के बैनर तले कश्मीर के पूर्ण विलय को लेकर आंदोलन चलाया था। पर टिकट बंटवारे को लेकर हाल के दिनों में पार्टी में विवाद सामने आये हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके निर्मल सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला है। इसलिए पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है। भाजपा के लिए एक अच्छी बात यह कही जा सकती है कि उसके पास कश्मीर घाटी की मुस्लिम बहुल जनसंख्या से भी लोग टिकट के लिए आये हैं। राज्य की कुल आबादी में 68 फीसदी मुसलमान हैं, जबकि हिंदू आबादी सिर्फ 28 प्रतिशत ही हैं। करीब दो फीसदी सिख भी हैं। माना जा रहा है कि हिंदुओं और सिखों का समर्थन भाजपा को मिलेगा। वैसे वह मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीते संसदीय चुनाव में यहां निर्दलीय इंजीनियर राशिद भी चुनाव जीत चुके हैं। माना जा रहा है कि अपने प्रभाव वाले इलाके में वे अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेंगे। अगर भाजपा को ठोस कामयाबी नहीं मिलती है, तो विरोधियों को मौका मिल जायेगा और उनकी आवाज बुलंद होगी। सीमापार की भारत विरोधी ताकतों को भी बोलने का अवसर मिल जायेगा।

अरिघाट क्यों है भारत के लिए ब्रह्मास्त्र

रंजीत कुमार

परमाणु मिसाइलों से लैस दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिघाट के भारतीय नौसेना में पिछले हफ्ते शामिल हो जाने के बाद भारत को वह ब्रह्मास्त्र मिल गया है, जिसे शायद ही कभी चलाने की जरूरत पड़े। समुद्र की तलहटी में महीनों चुपचाप विचरण करने की क्षमता वाली परमाणु पनडुब्बी के रूप में इसकी मौजूदगी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत पर कोई भी देश परमाणु हमला न कर पाए।

परमाणु पनडुब्बियों के विकास में मिली इस असाधारण कामयाबी से विश्व सामरिक जगत में भारत का दबदबा बढ़ेगा। आठ साल पहले 2016 में भारतीय नौसेना में परमाणु बिजली से चालित पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को शामिल किया गया था। आईएनएस अरिघाट, अरिहंत से अधिक क्षमतावान है। इसमें साढ़े तीन हजार किलोमीटर तक मार करने वाली चार परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें (के-4) लोड की जा सकती हैं। युद्ध की स्थिति में यह पनडुब्बी दुश्मन के समुद्र तट के काफी करीब छुपकर बैठ सकती है और दुश्मन के अहम ठिकानों पर वार कर सकती है। ऐसा हमला करने का निर्देश अरिघाट के कमांडर को तब मिलेगा, जब भारत पर परमाणु हमला हुआ हो और भारतीय सेनाएं अपनी जमीन आधारित अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल या फिर राफेल या सुखोई-30 विमानों से दुश्मन पर परमाणु बम गिराने की स्थिति में न हों।

परमाणु पनडुब्बी हासिल कर भारत ने परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता को और मजबूत किया है। इसकी मौजूदगी मात्र से दुश्मन देश भारत पर परमाणु हमला तो क्या पूर्ण स्तर का पारंपरिक युद्ध छेड़ने से भी हिचकेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु पनडुब्बियां अपनी ताकत की बदौलत शांति बनाए रखने के काम आएंगी।

भारत ने दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए वैसे तो

अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी परमाणु बम गिराने के लिए तैयार रखा है, लेकिन समुद्र आधारित परमाणु मिसाइलों की जरूरत इसलिए थी कि देश सेकंड स्ट्राइक यानी जवाबी हमला करने की स्थिति में हमेशा बना रहे। मई, 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत ने दुनिया को आश्वस्त किया था कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि किसी ने उस पर परमाणु हमला किया तो वह दुश्मन पर महाविनाशकारी हमला करने को स्वतंत्र होगा। अरिघाट हासिल करने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों- अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन- के क्लब में शामिल हो गया है, जो परमाणु त्रिकोण की ताकत रखते हैं। शायद यह भी एक वजह है कि पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर 50 हजार से अधिक सैनिकों की पिछले चार वर्षों से तैनाती जारी रहने के बावजूद चीन के साथ खुला युद्ध शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इसकी अंतिम परिणति परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल के रूप में हो सकती है।

अमेरिका की करीब 70 और चीन की करीब एक दर्जन परमाणु पनडुब्बी क्षमता के मद्देनजर भारत ने भी परमाणु पनडुब्बियों के संचालन की न्यूनतम क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना को करीब छह महीने बाद तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन मिलेगी। चौथी परमाणु पनडुब्बी का निर्माण भी चल रहा है। तुलनात्मक रूप में भारत का परमाणु पनडुब्बी बेड़ा काफी छोटा होगा, लेकिन दुश्मनों से निपटने के लिए फिलहाल इसे काफी माना जा रहा है।

परमाणु पनडुब्बी बनाने में भारत को अमेरिका या किसी पश्चिमी देश से सहयोग नहीं मिल सकता था, लेकिन इसके संचालन में रूस से अहम तकनीकी मदद मिली है। अरिहंत और अरिघाट के विकास में रूसी इंजिनियरों का काफी सहयोग मिला है। रूस अपनी दो परमाणु पनडुब्बियां भी भारत को लीज पर दे चुका है। 1989 में उसने पहली बार चार्ली वर्ग की पनडुब्बी दी थी, जिसका नाम चक्र-1 रखा गया था। इसका लीज समाप्त होने के बाद अकुला वर्ग की दूसरी परमाणु पनडुब्बी दस साल के लीज पर दी। अब रूस से दस साल के लीज पर एक और परमाणु पनडुब्बी लेने की बात चल रही है।

भारत को डीजल चालित पनडुब्बी के बेड़े का तेजी से विस्तार करने की जरूरत है क्योंकि भारत के पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े में फिलहाल 16 डीजल पनडुब्बियां ही हैं। फ्रांसीसी स्कॉरपीन वर्ग की अब तक मिली पांच पनडुब्बियों (छठी और अंतिम का निर्माण मुंबई में चल रहा है) के अलावा सभी पनडुब्बियां रिटायर होने की उम्र में हैं। इसलिए भारत को जल्द ही अपना पारंपरिक डीजल पनडुब्बी बेड़ा बढ़ाने का फैसला करना होगा।

सदी की शुरुआत में भारत ने तय किया था कि नौसेना के पास 2030 तक न्यूनतम 24 पनडुब्बियां होनी चाहिए। लेकिन नई डीजल पनडुब्बियां शामिल करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है और पुरानी 12 डीजल पनडुब्बियां अगले कुछ सालों के भीतर रिटायर करनी होंगी। परमाणु पनडुब्बी अरिघाट के शामिल होने से कुछ राहत मिलेगी लेकिन हिंद महासागर की समुचित चौकसी के लिए पनडुब्बी बेड़ा बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि भारत के समुद्री इलाके में चीनी नौसेना की हलचल पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ गई है।

भयावह होगी कर्ज में धंसते हिमाचल की सूरत

डा. रचना गुप्ता

हिमाचल जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य की माली हालत पर देश भर में खूब बवाल मचा है। करीब 70 लाख की आबादी वाले राज्य में सवा दो लाख कर्मचारी व उनके वित्तीय लाभ इतने हावी हो गए हैं कि प्रदेश में विकास पर ब्रेक लगना स्वाभाविक है। पूरे देश में मीडिया चैनलों पर हिमाचल के संकट का कारण ओल्ड पैंशन स्कीम यानी ओ.पी.एस. देने को माना जा रहा है। वहीं भाजपा को हरियाणा, जम्मू-कश्मीर में हो रहे चुनावों के मद्देनजर देश भर में कांग्रेस की इक्षखचाई का मौका हाथ लग गया है।

दरअसल हिमाचल की वित्तीय हालत का मसला कोई ज्यादा पेचीदा नहीं है। न ही कोई सरकार या एक पार्टी या एक राजनेता इस हालात के लिए दोषी है। साल दर साल राज्य की आर्थिक स्थिति को बिगडऩे से बचाने के प्रयास ही नहीं हुए। वहीं राज्य में सरकारी नौकरी के लालच में लोगों ने सरकार से वित्तीय अपेक्षाएं बढ़ा लीं। बैक डोर एंट्री से लेकर रैगुलर करने, एरियर, डी.ए., पैंशन तक का लाभ लेने की लालसा ने वित्तीय स्थिति का बेड़ा गर्क कर दिया। हां, कांग्रेस के गले यह विषय इसलिए पड़ गया क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ओ.पी.एस. देने का वादा किया, बगैर यह जाने कि राज्य यह सब देने की स्थिति में नहीं है। अब विधानसभा चुनावों व उप-चुनावों में हार के बाद भाजपा जाहिर तौर पर कांग्रेस का 'फ्रीबीज' का फार्मूला फेल करने के लिए सदन चलने भी कैसे देगी? लेकिन राज्य की गत कुछ वर्षों की वित्तीय स्थिति पर गौर करें तो स्थिति साफ हो जाती है कि पूर्व की कांग्रेस ही नहीं, भाजपा की सरकारों ने भी राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करने की बजाय कर्ज की बैसाखियां पहना कर रखीं। अब जब सुखविंद्र सुक्खू ने 'फ्री' बंद करना शुरू किया तो चीखो-पुकार होनी शुरू हो गई।

वीरभद्र, धूमल, जयराम या सुक्खू, सभी को हिमाचल की दुर्दशा का अंदाजा था, परंतु धृतराष्ट्र की पट्टी ने हिमाचल को इस मुहाने पर खड़ा कर दिया। अब वित्तीय तथ्यों का आकलन करें तो तस्वीर साफ है। वास्तव में वर्ष 2018-19 में जयराम ठाकुर ने भाजपा का पहला बजट पेश किया, तब 41,440 करोड़ का बजट था। सुक्खू ने 2022-23 का बजट दिया 53,413 करोड़ रुपए का। तब भी 50 प्रतिशत

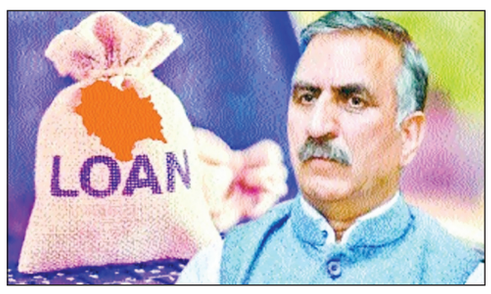

बजट सैलरी, पैंशन, एरियर, भत्तों में जाता था और अब भी वहीं जाता है। रही ऋण की स्थिति, तो 2007 में हिमाचल का उधार 1977 था, फिर 2012 में 27598, 2017 में 46,386, 2022 में 69,122 और 2024 में 86,589 (सभी करोड़ रुपए में) का ऋण हो गया।

जब जयराम ने सत्ता संभाली तो सरकार 3500 करोड़ रुपए तो सिर्फ वार्षिक ब्याज भरती थी। चूंकि पैंशन (ओ.पी.एस.) बंद हो गई, तब बजट में पैंशन का शेयर घट गया और ब्याज का भी घटा लेकिन ऋण उसी प्रतिशत के हिसाब से चलता रहा। अब हिमाचल की खराब वित्तीय हालत के लिए दो पहलू और बढ़ गए। केंद्र में विभिन्न दलों की सरकारों की हिमाचल के प्रति बेरुखी भी रही, तो वहीं प्रदेश में राजनेताओं के वोट बैंक के लालच ने सरकारी नौकरी व लाभ का प्रलोभन देकर रखा। चाहे कांग्रेस ने पी.टी.ए. टाइप कर्मी बैक डोर से रखे, फिर भाजपा ने पक्के कर दिए और अब ऐसे कई किस्म के कर्मी डी.ए., एरियर, पैंशन मांग कर नेताओं की कमजोरी भांप गए हैं।

सबसे पहला झटका हिमाचल को एन.डी.ए. के समय में लगा, जब प्रदेश की योजना में विकास का हिस्सा (केंद्र व राज्य का) आधा-आधा कर दिया गया। यानी 50-50 प्रतिशत शेयर। जिसे 2015-2018 के समय दौरान 90-10 प्रतिशत किया गया। परंतु तब तक कर्ज 47 हजार करोड़ रुपए हो चुका था।(सभी आंकड़े वित्तीय वर्षों में हिमाचल बजट लेखों से हैं।) लेकिन जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तब बहुत सारे फंड नाबार्ड व केंद्र प्रायोजित स्कीमों के प्रदेश को मिलते रहे, पर सैलरी व ऋण सिरदर्दी बने रहे। उन्होंने अपने चुनावी वर्ष के अंतिम कार्यकाल (2022-2023) में बजट प्रस्ताव को करीब 41 से 51 हजार करोड़ कर दिया। यानी बजट 5 साल में सीधा लगभग 11 हजार करोड़ बढ़ा दिया।

अब वर्ष 2022-2023 में सुक्खू की कांग्रेस सरकार का बजट आया। सरकार का घाटा बढ़ता गया। इस बीच पे- रिवीजन भी हो गया और ओ.पी.एस. का वादा भी निभाना था। बस इन्हीं दो मुद्दों पर गाड़ी पटरी से नीचे उतरनी शुरू हो गई। जब सुक्खू मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया, तब भाजपा सरकार सिर्फ पैंशन व एरियर की 10 हजार करोड़ देनदारी छोड़ गई थी। तब प्रदेश के हर व्यक्ति पर औसतन 92,833 रुपए का कर्जा हो गया था। यहां कांग्रेस सरकार को एक झटका और यह लगा कि 2022-23 में केंद्र से मिलने वाला घाटा अनुमान और कम हो गया। यह घटकर करीब 9,000 करोड़ ही मिला, जो अगले साल और घट कर 3,000 करोड़ ही मिलेगा। दूसरा संकट यह हो गया कि सत्ता में आते ही कांग्रेस को 2003 से रिटायर हो चुके 5,000 सरकारी कर्मियों को पैंशन देनी पड़ गई, वहीं, पुरानी पैंशन स्कीम (ओ.पी.एस.) का 8,000 करोड़ केंद्र सरकार ने वापस करना था, जो हिमाचल को मिला ही नहीं। एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. के बदलाव का झमेला गले पड़ा तो रिवाइज्ड पे-स्केल व एरियर सुक्खू को परेशानी में डाल गए। मार्च 2022 की कैग की रिपोर्ट में साफ किया गया कि हिमाचल को जयराम के मुख्यमंत्री रहते वक्त जी.एस.टी. का 4,412 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना था, वह भी नहीं मिला। वहीं पूर्व भाजपा सरकार के समय करीब 2,000 करोड़ रुपए विभिन्न स्कीमों के खर्च ही नहीं हुए। कुल मिलाकर पिछले वर्षों में राज्य सरकारें अपने बटुए को संभाल ही नहीं पाईं और अब कर्मचारियों का हल्ला बोल पूरे देश में सुन रहा है। केंद्र व राज्य में विभिन्न दलों की सरकारें होने का खामियाजा हिमाचल भुगत रहा है। इस बार पहली दफा पहली तारीख को कर्मियों को वेतन व पैंशन नहीं मिली। आने वाला समय (कुछ सालों के लिए) भयावह हो सकता है। खासकर तब, जब हिमाचल को इस चक्रव्यूह से केंद्र बाहर न निकाले। पर वह होगा नहीं क्योंकि ओ.पी.एस. का कांग्रेसी फार्मूला विरोधी पार्टियां कभी सफल नहीं होने देंगी और हिमाचल को 'फेलियर मॉडल' के तौर पर प्रस्तुत करती रहेंगी।

हारे उम्मीदवारों ने जोर लगाया तो फंसेगी दिग्गजों की सीट

निवेदिता वर्मा

हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में 17 सीटें ऐसी थीं, जहां जीत-हार का अंतर 600 से 3500 वोट रहा था। बहुत ही कड़े मुकाबले में विधायकों की सीट निकल पाई थी। कुछ ऐसी सीटें थीं, जहां बाजी पलटते-पलटते रह गई थी। इनमें कई दिग्गज भी शामिल हैं, जिनका राज्य की राजनीति में अच्छा खासा रुतबा है। इनमें भाजपा-कांग्रेस और अन्य दलों के विधायक शामिल हैं। पांच साल के बाद भी इन 15 सीटों पर सबकी नजरें हैं। इस बार भी मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। कम अंतर से हारे उम्मीदवारों को यदि टिकट मिलता है और वह जोर लगाते हैं तो इस बार कई दिग्गजों की सीट फंस सकती है। उनके लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। 2019 के चुनाव में सबसे कम अंतर से हरियाणा लोकहित पार्टी के संस्थापक गोपाल कांडा मात्र 602 अंतर से जीते थे। सिरसा विधानसभा सीट से उतरे गोपाल कांडा को 44915 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल सेतिया को 44313 वोट मिले थे। गोपाल कांडा भले ही कम अंतर से जीते हों, मगर आसपास की दो से तीन सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव है। वह कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। इसी तरह से दूसरे बड़े दिग्गज मेवात बेल्ट से आने वाले पुन्हाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास मात्र 816 वोट से जीते थे। उन्हें 35092 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान को 34276 वोट मिले। इलियास भजनलाल व चौटाला सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वह ही एक ऐसे नेता हैं, जो मेवात बेल्ट की तीनों विधानसभा सीट नूंह, फिरोजपुर झिरका व पुन्हाना से विधायक रह चुके हैं। तीसरे बड़े दिग्गज राज्य के निकाय मंत्री व थानेसर से विधायक सुभाष सुधा हैं, जो पिछला चुनाव मात्र 842 वोटों से जीते थे। चुनाव में उन्हें 55759 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा को 54917 वोट मिले। इस बार का चुनाव सुभाष सुधा के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। वहीं चौथे दिग्गज रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव हैं। वह अपना चुनाव मात्र 1317 वोटों से जीते थे। राव को 43870 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार को 42553 वोट मिले। राज्य की शिक्षा मंत्री व बड़खल से भाजपा विधायक सीमा त्रिखा की भी राह इस बार आसान नहीं होने वाली। वह अपना चुनाव मात्र 2545 वोट से जीती थी। कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। इसी तरह से रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार मनीष ग्रोवर से मात्र 2735 वोटों से जीते थे। उधर, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा भी भाजपा उम्मीदवार नागेंद्र भड़ाना से 3242 वोटों से जीते थे। मुलाना से विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरुण चौधरी मात्र 1688 वोटों से जीते थे। हालांकि वह अब सांसद बन चुके हैं। इसलिए कांग्रेस इस सीट से नया उम्मीदवार उतारेगी। यमुनानगर सीट से कांग्रेस विधायक बिशन लाल भी लड़खड़ाते हुए जीते थे। वह भाजपा उम्मीदवार कणदेव से मात्र 2541 वोटों से जीते थे। कैथल से भाजपा विधायक लीला राम ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को मात्र 1246 वोटों से हराया था। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने भाजपा के भगवान दास को मात्र 2222 वोटों से हराया था। इसी तरह से असंध से कांग्रेस विधायक शमेशर सिंह गोगी मात्र 1703 वोटों, राई से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली 2662 वोटों से, खरखौदा से कांग्रेस के जयवीर सिंह 1544 वोटों से, फतेहाबाद से भाजपा के दुर्गाराम बिश्नोई 3300 वोट, रतिया से लक्ष्मण नापा 1216 वोट, हथीन से भाजपा विधायक प्रवीण डागर मात्र 2887 वोटों से जीत हासिल की। वरुण चौधरी को छोड़कर बाकी सभी सीटों के विधायक व पिछला चुनाव हारे उम्मीदवार अपनी सीट से फिर से दावेदारी कर रहे हैं। इनमें से कई ऐसे दिग्गज हैं, जिनका टिकटा मिलना तय है। वहीं, हारे उम्मीदवार भी कम जीत के अंतर को आधार बनाकर हाईकमान के सामने मजबूती से दावा जता रहे हैं।

बैंकिंग सेक्टर में भी इस तरह बन सकते हैं लीडर

जरूरी नहीं कि हमेशा बॉस ही लीडर हो, कोई और भी लीडर हो सकता है। लीडरशिप का गुण ऑफिस में आपके व्यवहार में प्रतिबिंबित हो ही जाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी हर ब्रांच में एक लीडर की जरूरत होती है और बैंक ऑफिसर्स की भर्ती करने वाले इंटरव्यू पैनल ऐसे ही लीडर की तलाश में होते हैं। किसी बैंक ब्रांच में दूसरों का नेतृत्व करने के लिए कई गुणों की जरूरत होती है।

किसी भी सेक्टर में या किसी भी ऑफिस में, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को उनका काम करने में मार्गदर्शन देते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा बॉस ही लीडर हो, कोई और भी लीडर हो सकता है। लीडरशिप का गुण ऑफिस में आपके व्यवहार में प्रतिबिंबित हो ही जाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी हर ब्रांच में एक लीडर की जरूरत होती है और बैंक ऑफिसर्स की भर्ती करने वाले इंटरव्यू पैनल ऐसे ही लीडर की तलाश में होते हैं। किसी बैंक ब्रांच में दूसरों का नेतृत्व करने के लिए कई गुणों की जरूरत होती है। कारण यह कि बैंक में किसी भी दिन ऐसी कई स्थितियां बन सकती हैं, जिनमें संभव है कि ब्रांच मैनेजर भी न समझ पाए कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ब्रांच में कोई तो हो, जो रास्ता दिखा सके। एक बैंकर को अच्छा लीडर बनाने वाले गुण इस प्रकार हैं –

त्वरित बुद्धि

यह सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी पैसों संबंधी कोई समस्या उठ खड़ी होती है, तो अक्सर लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। आखिर सवाल रुपए-पैसों का जो है! ऐसी स्थिति में एक लीडर की त्वरित बुद्धि के चलते उसके समक्ष एक नहीं, अनेक उपाय उठ खड़े होंगे। तब वह उनमें से श्रेष्ठ उपाय को चुनकर लागू करेगा।

ठंडा दिमाग

लीडरशिप के लिए यह बहुत जरूरी होता है। बैंकिंग में आपका पाला कई लोगों से पड़ेगा और सब एक जैसे नहीं होंगे। ऐसे भी लोग होंगे, जो बैंक में आकर आपसे या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य से बहस करेंगे लेकिन ऐसे में आपको अपना संतुलन नहीं खोना है। याद रखें, वह व्यक्ति तो अपना काम कराकर चला जाएगा लेकिन यदि आप गरम दिमाग से दिन भर काम करेंगे, तो आपसे जरूर कोई-न-कोई गलती हो ही जाएगी! इसलिए लीडर के लिए हर हाल में शांत बने रहना जरूरी है। वैसे भी ग्राहक तो ग्राहक होता है और बैंक कर्मचारी के तौर पर आपका काम उसकी सेवा करना ही है।

लचीलापन

लीडर होने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी मर्जी से लोगों को हांक लेंगे। यह संभव नहीं कि किसी के पास हर समस्या का समाधान हो। हो सकता है कि आपके पास किसी समस्या का समाधान न हो लेकिन किसी और के पास यह होगा। आपको उस शख्स की मदद लेनी होगी ताकि काम हो सके। एक सच्चा लीडर इतना लचीलापन हमेशा रखता है।

अच्छे संबंध रखें

बैंकिंग में यह बहुत जरूरी है क्योंकि बैंकिंग का व्यवसाय मूल रूप से विश्वास पर ही टिका होता है। आपको ब्रांच के हर कर्मचारी तथा ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने होते हैं। इससे ब्रांच में माहौल सकारात्मक बना रहता है।

दूसरों का सहारा बनें

गलती हर किसी से होती है और बैंकिंग में होने वाली गलती पैसे से जुड़ी ही होगी। बैंकर के रूप में, आपको जरूरत के समय अपने साथियों का साथ देना चाहिए। इससे उनकी नजरों में आप सच्चे लीडर होंगे।

लगन व परिश्रम

लीडर होने का मतलब है दूसरों के लिए मिसाल पेश करना और लगनशील व परिश्रमी होने की मिसाल से बेहतर क्या हो सकता है? जब साथी आपको मेहनत कर परिणाम प्राप्त करते देखेंगे, तो वे भी ऐसा ही करने को प्रेरित होंगे।

औरों से दो कदम आगे रहें

बैंकिंग जैसे प्रतिस्पधी क्षेत्र में यह बहुत जरूरी है कि लीडर अपनी सोच और अपने व्यवहार में दूसरों से हमेशा दो कदम आगे रहे। तभी तो वह अपने संस्थान को आगे ले जा पाएगा।

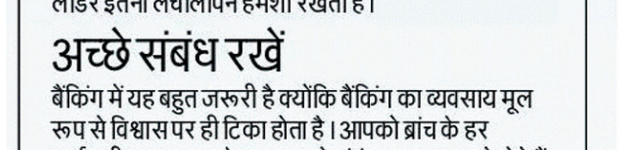

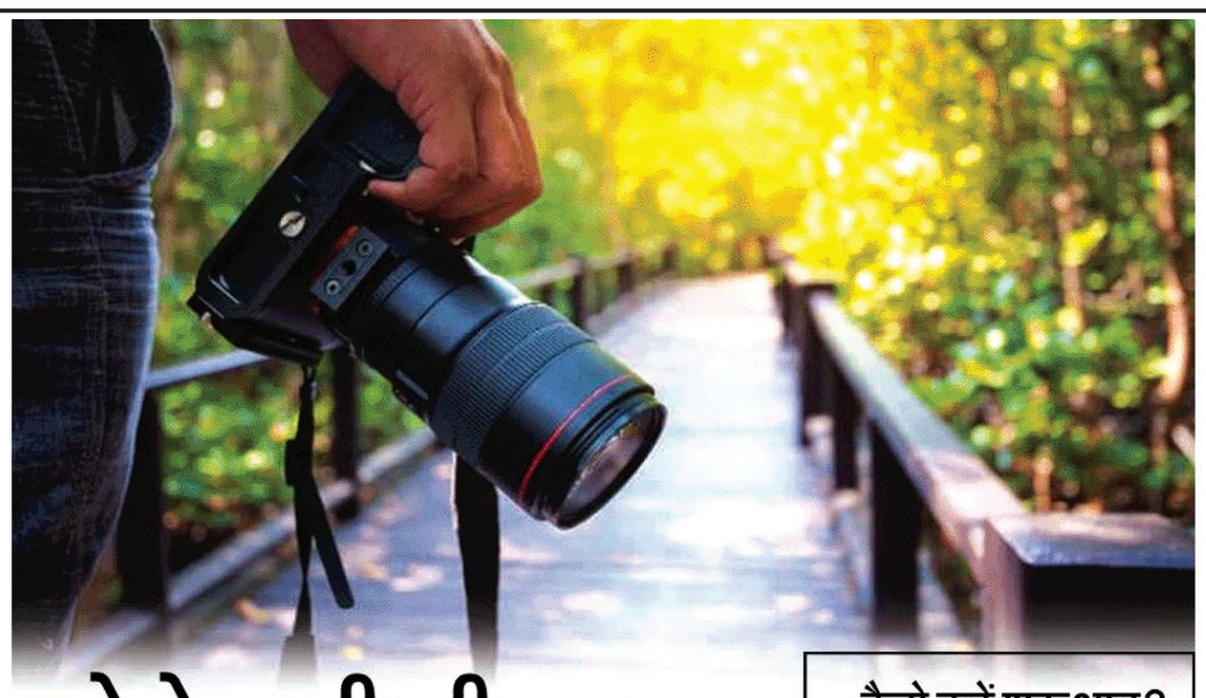

फोटोग्राफी की इन शाखाओं में बना सकते हैं शानदार करियर

फोटोग्राफी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी बात को कहने में जहां हजार शब्दों की जरूरत पड़ सकती है, वहीं एक फोटो हजार शब्दों को बयां कर देता है। फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए इस फील्ड में अनुभव के साथ इसका शौक होना भी बहुत जरूरी है। यह क्षेत्र न सिर्फ अच्छा पैसा देता है, बल्कि ग्लैमर से भी जुड़ा हुआ है।

क्या आपमें है धैर्य?

इस क्षेत्र में सफल होने के लिए एक मूलमंत्र है धैर्य। अच्छे क्लिक के लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है। फिर चाहे आप किसी भी माहौल में काम कर रहे हों। तनावपूर्ण माहौल हो या भीड़ भरे इलाके, फोटोग्राफर को अच्छा परिणाम देने में सक्षम होना पड़ता है। फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर के लिए अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। उसके लिए उसका कैमरा ही उसकी आंखें है। इसके अलावा, फ्रीलांस फोटोग्राफर या व्यवसायिक फोटोग्राफरों के पास तकनीकी कौशल के साथ व्यापारिक समझ भी होनी चाहिए। तकनीकी पहलू लाइटिंग, लैंस, रिफ्लेक्टर, फिल्टर और सेटिंग्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ही फोटोग्राफर किसी पिक्चर को कैप्चर करते हैं। इसी के साथ अच्छी फोटो खींचने के लिए कई चीजों के समायोजन की जरूरत होती है, जैसे कैमरे की क्वॉलिटी, सब्जेक्ट, लाइटिंग, फोटोग्राफर का कौशल आदि। डिजिटल कैमरों में इलेक्ट्रॉनिक मेमरी का इस्तेमाल किया जाता है। इन तकनीकों की जानकारी होना आज के समय में जरूरी है।

फोटोग्राफी की शाखाएं

फोटोग्राफी की कुछ खास शाखाएं हैं, जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ये इस प्रकार हैं –

विज्ञापन/ फैशन – विज्ञापनों और विज्ञापन एजेंसियों के कार्य के लिए कुशल फोटोग्राफरों की जरूरत होती है। फैशन फोटोग्राफी काफी हद तक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के समान ही होती है लेकिन इसमें तकनीक से ज्यादा परिधानों को उजागर करने की क्षमता जरूरी होती है।

कला/ फिल्म – आजकल किसी भी फिल्म की मेकिंग से लेकर उसके प्रदर्शन तक सारी गतिविधियां कैमरे में कैद की जाती हैं। इसके लिए हाई क्वॉलिटी और हाई रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है।

साइंस/ मेडिकल/ तकनीक – इन क्षेत्रों में कार्यरत फोटोग्राफर कला से ज्यादा महत्व वस्तुपरक दृष्टिकोण को देते हैं, जिससे तथ्य को समझने में आसानी हो सके। फॉरेन्सिक लैब हो या वारदात का स्थान, सभी जगह कई एंगलों से फोटो खींचने होते हैं।

फोटो जर्नलिज्म – अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो तुरंत घटनास्थल तक पहुंचने के साथ ही सबसे पहले प्रेस या स्टूडियो तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको ही निभानी होती है। फोटो जर्नलिज्म में फोटो की श्रृंखलाओं के माध्यम से किसी विषय या घटना के बारे में स्टोरी फाइल की जाती है। आज के डिजिटल दौर में विश्व की प्रमुख घटनाओं को फोटो के माध्यम से कवर करने का रुझान तेजी से बढ़ा है।

कैसे करें शुरूआत?

बारहवीं या ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में प्रवेश लिया जा सकता है। इस कोर्स को सरकारी या निजी स्तर पर कई संस्थान कराते हैं। कोर्स करने से पहले बेसिक फोटोग्राफी का ज्ञान हासिल कर लेना अच्छा रहता है। बेहतर होगा कि एक डिजिटल कैमरा लेकर इसकी शुरूआत कर दी जाए। जब आपको लगे कि आप इस कोर्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो फिर डिजिटल एसएलआर खरीदकर प्रोफेशनली इससे जुड़ जाएं।

प्रशिक्षण भी अहम

फोटोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए किसी अच्छे संस्थान से फाइन आर्ट्स या मास कम्युनिकेशन कोर्स करके अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वहीं मोशन फोटोग्राफी का प्रशिक्षण फिल्म एवं टेलीविजन संस्थानों द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश लेना जरूरी है। इनमें फोटोग्राफी कला का अध्ययन कराया जाता है। इससे आपको मूलभूत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जब आपको लगे कि आप पर्याप्त सक्षम हो गए हैं, तो किसी एक्सपर्ट फोटोग्राफर के साथ काम कर बारीक चीजों को भी सीख सकते हैं। फिर उच्च शिक्षण संस्थान की ओर रुख कर सकते हैं। यदि यह तरीका न भाए, तो दूसरे तरीके से फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जैसे कोर्स में प्रवेश लें। इसमें आपको फोटोग्राफी मुख्य कोर्स के तौर पर पढ़ाई जाएगी। ध्यान रहे, प्रशिक्षण आपको तकनीकी पहलुओं की जानकारी दे सकता है लेकिन नए विचार और व्यक्तिगत स्टाइल तो स्वयं ही विकसित करनी होती है। व्यवहारिक ज्ञान यहां सबसे जरूरी होता है।

इन टिप्स को अपनाकर बन सकते हैं एक अच्छा मैनेजर

किसी भी संस्थान में एक मैनेजर की अहम भूमिका होती है। अगर आप भी अपने करियर में आगे बढ़ते हुए इस पद पर पहुंच गए हैं या पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र के अलावा और भी चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स की असली परीक्षा यही देनी होती है। एक लीडर के रूप में आप सभी सफल हो सकते हैं जब आपके कर्मचारी आपके साथ खुश, प्रेरित और उत्साहित महसूस करें।

कर्मचारियों को प्रेरित करना

अगर आप अपनी टीम का सम्मान करेंगे तो वे आपका सम्मान करेंगे। आपको उनकी हर छोटी-बड़ी चीजों का एप्रिशियेट करना होगा। उनसे अपने काम की ही फीडबैक न लेते रहें, बल्कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को शेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

फील गुड कराएं

कर्मचारियों से केवल काम लेना है, ऐसी सोच आपके अच्छे मैनेजर बनने का गुण नहीं है। एक सफल मैनेजर में अपने कर्मचारियों की अच्छी बातों और क्षमताओं को पहचाने की समझ होती है। उनका मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें ऐसा माहौल दें कि वे बेहिचक काम कर सकें।

पीठ पीछे भी प्रशंसा

आपको उनके काम, व्यवहार, उदारता की तारीफ उनके सामने तो करनी ही चाहिए। साथ ही आपको उनके पीठ पीछे भी तारीफ करना चाहिए। एक कर्मचारी जो जानता है कि उसकी कितनी प्रशंसा की जाती है तो वह ज्यादा मेहनत करेगा, अपने काम में ज्यादा आनंद लेगा और इस मानसिक खुशी को वह दूसरे कर्मचारियों के साथ बांटेगा।

जिम्मेदारी सौंपे

आप एक मैनेजर है क्योंकि आप अपने काम में एक्सपर्ट है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सारा काम खुद करना है। आपको यह समझ होनी चाहिए कि कौन सा काम, कौन सा कर्मचारी बखूबी पूरा कर सकता है। आपको अपने कर्मचारी को सीखने और नए अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे-धीरे जैसे आप उनकी सक्षमता और कमजोरियों को समझने लगें उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी के काम सौपें।

मैथ्स में है रूचि तो इन क्षेत्रों में बना सकते हैं करियर

गणित मनुष्य के ज्ञान की एक अत्यधिक उपयोगी तथा आकर्षक शाखा है। इसमें अध्ययन के कई विषय शामिल हैं। भारत में प्राचीन काल से ही गणित की एक सुदृढ़ परंपरा रही है और आज भी यहां गणित में विश्व स्तर के अनुसंधान करने वाले अनेक संस्थान हैं। गणनाओं में रुचि रखने वाले युवा बड़ी संख्या में गणित को करियर के रूप में चुनते हैं। गणित लगभग सभी वैज्ञानिक अध्ययनों का एक अनिवार्य अंग है। वैज्ञानिक गणित का उपयोग प्रयोगों की रूपरेखा बनाने, सूचना का विश्लेषण करने, गणित के सिद्धांतों द्वारा अपने निष्कर्ष उचित रूप में व्यक्त करने तथा इन निष्कर्षों के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान जैसे विषय तो गणित पर ही निर्भर हैं। सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग आदि भी गणित की ही शाखाओं पर निर्भर होते हैं।

भारत में 135 से भी अधिक विश्वविद्यालय गणित से जुड़े कोर्स चलाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय शुद्ध गणित (प्योर मैथमेटिक्स) व अनुप्रयुक्त गणित (अप्लायड मैथमेटिक्स) में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। आप कुछ स्थानों पर चलाए जाने वाले एकीकृत एमएससी पीएचडी डिग्री कोर्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यूं देश में स्नातक स्तर पर गणित की शिक्षा देने वाले दो विश्व स्तरीय संस्थान हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), बेंगलुरू तथा चेन्नाई गणित संस्थान (सीएमआई), चेन्नाई। आईएसआई से गणित व कम्प्यूटर विज्ञान में बी. मैथ्स डिग्री तथा सीएमआई से गणित की बीएससी डिग्री की जा सकती है। इनमें प्रवेश प्रत्येक वर्ष मई के अंत में देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली एक लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। ये दोनों संस्थान ऐसे विद्यार्थियों को भी अपने यहां प्रवेश देते हैं, जो इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलिंपियाड (आईएनएमओ) में पास होते हैं या किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) अध्येता होते हैं। गणित में विशेषज्ञतापूर्ण कोर्स चलाने वाले देश के अन्य प्रमुख संस्थान इस प्रकार है –

- औद्योगिक गणित में पाठ्यक्रम पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में उपलब्ध है।
- न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स पाठ्यक्रम मदुरै कामराज विश्वविलय, मदुरै में उपलब्ध है।
- गणितीय अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में उपलब्ध है।

इसके अलावा एमएससी व पीएचडी कोर्स के लिए देश के प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं – टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई। लिखित परीक्षा तथा उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर), पुणे/ मोहाली/ कोलकाता/ तिरुवनंतपुरम/ भोपाल तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईएसईआर), भुवनेश्वर में भी गणित में एकीकृत एमएससी डिग्री कोर्स उपलब्ध है।

आईआईएसईआर विद्यार्थियों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देता है, जबकि एनआईएसईआर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट (एनईएसटी) के माध्यम से प्रवेश देता है।

हैदराबाद विश्वविलय द्वारा गणित में एकीकृत एमएससी पाठ्यक्रम चलाया जाता है। यह विश्वविद्यालय जून के आरंभ में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देता है।

विषय एक संभावनाएं अनेक

गणित तथा इससे जुड़े प्रमुख करियर इस प्रकार हैं

गणितज्ञ

गणितज्ञों को गणित का अध्ययन अथवा अनुसंधान करना होता है। वे गणित के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं।

शिक्षण

गणित के शिक्षकों की मांग कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। गणित पूरी स्कूली शिक्षा में एक मुख्य विषय होता है। यदि आपमें संख्याओं के प्रति गहरा आकर्षण है और विद्यार्थियों को पढ़ाने में आपकी रुचि है, तो आप शिक्षण के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले गणितज्ञों का अध्यापन तथा अनुसंधान में खास योगदान होता है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में धूम मची हुई है। वैश्विक आईटी इंडस्ट्री भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर के प्रयोग तथा उनकी प्रणाली का सृजन, परीक्षण, विश्लेषण व मूल्यांकन करने के लिए कम्प्यूटर विज्ञान और गणितीय विश्लेषण के सिद्धांतों को कार्यान्वित करते हैं।

बैंकिंग

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के चलते बैंक तेजी से अपनी शाखाएं बढ़ा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। गणित में महारथ रखने वाले युवा बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट

उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के चलते अकाउंट्स तथा फाइनेंस के क्षेत्र में करियर ने खूब लोकप्रियता अर्जित की है। इस क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक अत्यधिक प्रतिष्ठित करियर विकल्प है। मैथ्स व कॉमर्स में रुचि रखने वाले युवा इस क्षेत्र में बढ़िया करियर बना सकते हैं।

कम्प्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट

कम्प्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट के लिए सॉफ्टवेयर, अनुसंधान, शिक्षा, सिक्यूरिटी, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिकी, तकनीकी शाखाओं आदि में रोजगार के ढेरों अवसर हैं। अधिकांश सिस्टम्स एनालिस्ट लागत-लाभ व निवेश पर मुनाफा का विश्लेषण तैयार करने के लिए विशिष्ट प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियों पर कार्य करते हैं और मैनेजरों को यह निर्णय लेने में सहायता करते हैं कि या प्रस्तावित टेक्नोलॉजी वित्तीय दृष्टि से कारगर होगी या नहीं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

6 को जम्मू-कश्मीर के लिए घोषणापत्र जारी करेंगे शाह

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छह सितंबर से जम्मू के दो दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वह भाजपा का घोषणापत्र जारी करेंगे और राजनीतिक रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह भाजपा के चुनावी अभियान की शुरूआत करेंगे। उनकी यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पार्टी सूत्रों का मानना है कि उनकी उपस्थिति उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं दोनों के लिए मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। सितंबर के मध्य में शाह के कश्मीर दौरे पर जाने की भी उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर चुनाव में भाजपा को कांग्रेस-एनसी गठबंधन का सामना करना है। जम्मू क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है। इसे बचाने की भाजपा को चुनौती रहने वाली है। जम्मू-कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे।

दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी इच्छाशक्ति चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ये बयान अखिलेश यादव की उस टिप्पणी के जवाब में दिया है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि सत्ता में आए तो 2027 के बाद बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं। कुछ समय पहले एक नाटक आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आज वह लोग भी सपने देख रहे हैं। यह लोग सपना देख रहे हैं। जब इनको अवसर मिला था तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक व फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे।

आरोप लगाने से पहले 'डीएनए' का फुल फॉर्म तो जान लेते

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के 'डीएनए' के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें 'डीएनए' का फुल फॉर्म जान लेना चाहिये। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें ज्यादा सुनना भी पड़ता है। दरअसल आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुख्य विपक्षी दल सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर राज्य के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली सपा के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी पैबस्त है। इस पर यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो भी बोल न पाते। उन्होंने कहा, अरबों-करोड़ों में सांसद-विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग, जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्ज़त है।

राहुल गांधी से मिले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट

नईदिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर हैं। हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा, आप, इनेलो और जजपा में होगा। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी 90 में से 10 सीट की मांग कर रही है जबकि कांग्रेस सिर्फ सात सीटें देने को तैयार है। इस बीच राहुल गांधी ने पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से मुलाकात की। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की बुधवार सुबह राहुल गांधी के साथ मुलाक़ात हुई है। बजरंग पुनिया अगर बादली सीट से लड़ेंगे तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स की टिकट कट सकती है। वही विनेश के पास बारड़ा (घर) और जुलाना (ससुराल) दो विकल्प हैं। हरियाणा के चुनावी दंगल में हाथ आजमाने की अटकलों के बीच पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने बुधवार को यहां राहुल गांधी से मुलाकात की।

संख्या बल के अनुसार होगा मुख्यमंत्री का फैसला : पवार

मुंबई। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से तैयारी में जुट गई हैं। बैठकों के दौर जारी हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार ने इस पद के चेहरे को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोल्हापुर में कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पहले यह देखना होगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे, उसके बाद संख्या बल के अनुसार फैसला होगा। शरद पवार ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला संख्या बल के आधार पर होगा। शरद पवार ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य स्थिर सरकार देना है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में अभी सोचने की कोई वजह नहीं है, संख्या बल के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर की रैली में बोले राहुल गांधी

'इंडिया' गठबंधन के घटक दल जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली सुनिश्चित करेंगे

श्रीनगर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में अपनी पार्टी के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत की और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के सहयोगी दलों की मदद से केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के दर्जे की बहाली सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा, ''हम विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसके लिए तैयार नहीं थी और वह चाहती थी कि पहले चुनाव हो जाएं।''

रामबन में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार राज्य का दर्जा छीना गया है। केंद्र शासित प्रदेश को पहले राज्य बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक राज्य को खत्म कर दिया गया है और लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस करना होगा क्योंकि न केवल आपका राज्य छीना गया है, बल्कि आपके अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ आपसे छीना जा रहा है।

राहुल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया। आज जम्मू-कश्मीर में एक राजा हैं, उनका नाम है एलजी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। उनका काम नफरत फैलाने का है और हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। उन्होंने कहा कि वो तोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं। नफरत को मोहब्बत से ही हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंत में मोहब्बत की ही जीत होती है। पहले नरेंद्र मोदी छाती फैलाकर आते थे और अब झुककर आते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ- नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ- मोहब्बत और सम्मान। उन्होंने कहा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, जिसमें हमने नारा दिया- नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने कहा तकि हमारा पहला कदम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा। हम चाहते थे कि आपको चुनाव से पहले राज्य का दर्जा मिले और चुनाव जम्मू-कश्मीर राज्य बनने के बाद हों। बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। वे चाहते थे कि पहले चुनाव हो और फिर राज्य की बात हो। बीजेपी चाहे या न चाहे, इंडिया गठबंधन उन पर दबाव बनाएगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा मिलेगा।

रामबन जिले में तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 25 अन्य क्षेत्रों के साथ 18 सितंबर को मतदान होना है। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवार सज्जाद शाहीन और भाजपा के सलीम भट से कड़ी चुनौती मिल रही है। पूर्व मंत्री वानी इस सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं।

भारत, ब्रुनेई ने नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और ब्रुनेई ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत निरंतर नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के ब्रुनेई में स्थापित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं टेलीकमांड (टीटीसी) केंद्र को जारी रखने के लिए ब्रुनेई दारुस्सलाम की भरपूर सराहना की। इस केंद्र से भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में जारी उसके प्रयासों में मदद मिली।

संयुक्त बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी, ब्रुनेई के सुल्तान ने संयुक्त अभ्यास के जरिए रक्षा एवं समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। बयान के अनुसार, ''दोनों नेताओं ने शांति, स्थिरता, समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने एवं बढ़ावा देने के साथ नौवहन एवं उड़ान की स्वतंत्रता का सम्मान करने एवं अंतरराष्ट्रीय कानून विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) 1982 के अनुरूप निर्बाध वैध व्यापार की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।''

द्विपक्षीय बैठक के दौरान मोदी और सुल्तान बोलकिया ने कई विषयों पर चर्चा की और कारोबारी संबंध में और विस्तार, वाणिज्यिक संबंध और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के बारे में बात की। इससे पहले सिंगापुर के लिए रवाना होने से पहले मोदी ने ब्रुनेई की अपनी यात्रा को ''सार्थक'' बताया और कहा कि इससे ''भारत-ब्रुनेई संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नए युग'' की शुरुआत हुई है, जो हमारी धरती को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

द्विपक्षीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत और ब्रुनेई ने ''साझेदारी बढ़ाने के लिए'' द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। इस वर्ष हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने अपने संबंधों को एन्हांस पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ-साथ फिनटेक और साइबर सुरक्षा में आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक रूप से विचार किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए हमने उपग्रह विकास, रिमोट सेंसिंग और प्रशिक्षण पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए महामहिम और पूरे शाही परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन हर पल हम यहां दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास कर रहे हैं। इस वर्ष ब्रुनेई की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ है, आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है... 140 करोड़ भारतीयों की ओर से, मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

90000 करोड़ रुपये का निवेश, पीएम मोदी के सिंगापुर पहुंचने से पहले ही हो गया बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से सिंगापुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। ब्रुनेई से पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी 4 और 5 सितंबर की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। पीएम मोदी के सिंगापुर पहुंचने से पहले भारत के लिए अच्छी खबर आई है। एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक कैपिटालैंड अगले चार साल में भारत में निवेश की रकम दोगुनी करेगा। सिंगापुर के कैपिटालैंड इन्वेस्टमेंट ने बुधवार को कहा कि उसका लक्ष्य 2028 तक भारत में प्रबंधन के तहत अपने फंड को 30 जून तक 7.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर (5.66 बिलियन डॉलर) से दोगुना करने का है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को सिंगापुर पहुंचने से कुछ घंटे पहले की गई है। रियल एस्टेट निवेश प्रबंधक ने कहा कि यह 2028 तक कंपनी के FUM में S200 बिलियन प्राप्त करने के वैश्विक लक्ष्य में योगदान देगा। समूह के सीईओ ली ची कून ने कहा कि देश गुणवत्तापूर्ण वास्तविक संपत्तियों के लिए वैश्विक निगमों और संस्थागत निवेशकों की मांग को आकर्षित कर रहा है। कून ने कहा कि कंपनी देश में नवीकरणीय ऊर्जा और रियल एस्टेट निजी ऋण क्षेत्रों में प्रवेश करने के अवसर तलाशेगी। पिछले महीने, कंपनी ने भारत में बिजनेस पार्क विकास के लिए एक फंड लॉन्च किया था, जिससे प्रबंधन के तहत उसके फंड में S700 मिलियन जुड़ने की उम्मीद थी।

खेल
प्रमुख समाचार

सचिन सरजेराव ने पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में जीता रजत

पेरिस। भारत ने बुधवार को पदकों का खाता पुरुषों की एफ46 गोला फेंक स्पर्धा में खोला। सचिन सरजेराव खिलाड़ी ने 16.32 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। सचिन बस 0.06 मीटर से स्वर्ण पदक चूक गए। सचिन ने दूसरे प्रयास में ही 16.32 मीटर का थ्रो किया था। हालांकि, वह इससे ऊपर निकलन में कामयाब नहीं हो सके। कनाडा के ग्रेग स्टीवर्ट ने 16.38 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में भारत के मोहम्मद यासेर आठवें और रोहित कुमार नौवें स्थान पर रहे।

गोला फेंक के फाइनल में सचिन का पहला प्रयास 14.72 मीटर, दूसरा प्रयास 16.32 मीटर, तीसरा प्रयास 16.15 मीटर, चौथा प्रयास 16.31 मीटर, पांचवां प्रयास 16.03 मीटर और छठा (आखिरी) प्रयास 15.95 मीटर का रहा। उन्होंने 16.32 मीटर के थ्रो के साथ एरिया रिकॉर्ड भी बनाया। यह भारत का पेरिस पैरालंपिक 2024 में 21वां पदक रहा। सचिन ने 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट एफ46 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।उन्होंने 16.21 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया था। उन्होंने 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भाग लिया , जिसमें उन्होंने इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। यासेर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 14.21 मीटर का और रोहित का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 14.10 मीटर का रहा। पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाओं में एफ46 श्रेणी उन लोगों के लिए है जिनकी एक या दोनों भुजाओं की गतिविधि मामूली रूप से प्रभावित है या जिनके हाथ-पैर नहीं हैं। इन एथलीटों को कूल्हों और पैरों की ताकत से थ्रो करना होता है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले सचिन स्कूली दिनों में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिससे उन्होंने कोहनी की मांसपेशियां गंवा दी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद

नईदिल्ली। लगातार 14 दिनों की तेजी दर्ज करने के बाद एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 आज 0.32% या 81.15 अंकों की गिरावट के साथ 25,198.70 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, 30 शेयरों वाले एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट बरकरार रही। सेंसेक्स पर 30 में से सिर्फ 11 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि निफ्टी 50 पर हरे निशान में बंद होने वाले शेयरों की संख्या 18 रही। एचडीएफसी लाइफ के शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान आज सेंसेक्स 82,408.54 के हाई 81,833.69 के लो लेवल पर तो वहीं 25,216 के हाई और 25,083.80 के लो लेवल तक ट्रेड किया था। बीएसई पर आज कुल 4,047 शेयरों पर ट्रेड किए गए, जिसमें से 2,043 शेयरों में गिरावट आई। जबकि, एनएसई पर कुल ट्रेड 2804 हुए। जिसमें से 1,401 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 5 महीने के हाई पर

नईदिल्ली। भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि अगस्त में जुलाई की तुलना में बढ़ी। इसमें मार्च के बाद से सबसे तेज विस्तार देखा गया। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जुलाई में 60.3 से बढ़कर अगस्त में 60.9 हो गया। यह मार्च के बाद सबसे तेज विस्तार है। इसे काफी हद तक उत्पादकता लाभ और सकारात्मक मांग के रुझान से समर्थन मिला। खरीद प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, ''भारत के लिए समग्र पीएमआई में अगस्त में मजबूत वृद्धि रही जो सेवा क्षेत्र में त्वरित व्यावसायिक गतिविधि से प्रेरित है।

क्रेडिट कार्ड का बाजार 2028-29 तक हो सकता है दोगुना

नई दिल्ली। भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या 15 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर के साथ 20 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड उद्योग ने पिछले पांच वर्षों में जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की संख्या को दोगुना करते हुए महत्वपूर्ण विस्तार हासिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गति जारी रहने की उम्मीद है, आने वाले वर्षों में बाजार यह वृद्धि दोहरा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में क्रेडिट कार्ड बाजार में वित्त वर्ष 28-29 तक कार्डों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है, और यह आंकड़ा 20 करोड़ कार्ड तक पहुंच जाएगा। क्रेडिट कार्ड उद्योग में पिछले पांच वर्षों के दौरान 100 प्रतिशत की वृद्धि दिखी है। अगले पांच वित्तीय वर्षों के भीतर बाजार इस वृद्धि को दोहरा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने के अलावे इनसे होने वाली लेन-देन गतिविधियों में भी पर्याप्त वृद्धि आई है।

ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की जरूरत

नईदिल्ली। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में नये विचार लाने तथा युवाओं को शामिल करने के लिए स्टार्टअप लाने की जरूरत पर बुधवार को जोर दिया। 'ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया' 2024 के दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि 11 से 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में 120 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ''ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्टार्टअप लाने की जरूरत है क्योंकि इसके लिए युवा तथा नए विचारों की आवश्यकता है।'' इस आयोजन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रदर्शनी में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित 120 से अधिक दुकानें (स्टॉल) होंगी।

भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

जर्मनी एवं चीन भी अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जापान एवं जर्मनी में यदि विकास की रफ्तार कम होती है एवं भारत की आर्थिक विकास दर यदि इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है तो शीघ्र ही भारत, जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान एवं जर्मनी ही भारतीय अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बने हुए हैं।

अर्थ से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत सराहनीय प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे -

(1) पिछली तिमाही में भारत के निर्यात में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि दर केवल एक प्रतिशत की रही है।

(2) बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों में लगातार वृद्धि दर 15 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में ऋण की मांग (जुलाई 2024 में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर) एवं विनिर्माण के क्षेत्र में ऋण की मांग (जुलाई 2024 में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर) बनी हुई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के तेज गति से आगे बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।

(3) वित्तीय वर्ष 2024-25 में जुलाई 2024 माह के अंत तक समाप्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार की कुल आय 10.23 लाख करोड़ रुपए की रही है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय के कुल बजट का 31.9 प्रतिशत है और इसमें 7.15 लाख करोड़ रुपए की करों की मद से आय तथा 3.01 लाख

करोड़ रुपए की अन्य मदों से आय भी शामिल है।

(4) इस दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण में रहा है एवं यह 2.77 लाख करोड़ रुपए तक सीमित रहा है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजटीय घाटे का केवल 17.2 प्रतिशत ही है।

(5) इसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार भी 23 अगस्त 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में 702 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 68,168 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नए रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 454 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 67,466 करोड़ अमेरकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था।

(6) जुलाई 2024 माह में 8 कोर सेक्टर (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, इस्पात, सिमेंट एवं बिजली उत्पादन के क्षेत्र) में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत की रही है जो जून 2024 माह में 5.1 प्रतिशत की रही थी।

(7) भारत में प्रत्येक 5 दिनों में एक बिलिनायर (भारतीय नागरिक जिसके पास 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति है) बन रहा है। 2014 में भारत में 109 बिलिनायर थे जो आज बढ़कर 334 हो गए हैं। जिनकी कुल सम्पत्ति 1.9 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की है जो सऊदी अरब के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। इसी प्रकार, भारत के बिलिनायर की सम्पत्ति भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के आधे से भी अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था तो प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है परंतु यदि यह सम्पत्ति केवल बिलिनायर की संख्या बढ़ाने के रूप में बढ़ रही है तो यह उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे तो देश में अमीरों एवं गरीबों के बीच में असमानता की खाई भी बढ़ती जा रही है और इस खाई को शीघ्र ही पाटने के प्रयास किए जाने चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में कम हुई आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या अब भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी कर सकता है। अब यह प्रश्न अर्थशास्त्रियों के मन में उभर रहा है। इस बीच अमेरिका में भी फेड रिजर्व के अध्यक्ष ने अमेरिका में ब्याज दरों को सितम्बर 2024 माह में कम करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों को मजबूत नेटवर्क होगा तैयार

हर पंचायत में होगी सहकारी समितियां

पेक्स को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं श्री कुलदीप शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, ने 'सहकार से समृद्धि' पर बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर पंजीयक एच के दोशी, अपर पंजीयक एच के नागदेव,अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक श्री के.एन. काण्डे, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, दुग्ध महासंघ मत्स्य महासंघ, कॉमन सर्विस सेंटर व प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के राज्य प्रभारी व प्रतिनिधियों सहित अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन कर सक्रिय करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी छह-छह माह का लक्ष्य बनाकर पेक्स को मबजूत करने तथा मल्टी एक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ाने के दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि पेक्स को मल्टी परपस पेक्स के रूप में विकसित करने से लोगों के लिए घर के द्वार पर ही अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, गरीबों और मजदूरों के समय और पैसे की बचत होगी। आगामी खरीफ फसल की खरीदी का समय नजदीक आ रहा है। अत: सभी समितियों के पुराने कार्यों का ऑडिट अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वर्तमान में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केन्द्र हैं। ऐसे ग्राम पंचायत अथवा ऐसे स्थान जहां दूरी अधिक है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एवं रूपे क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के किसानों इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की समीक्षा करते हुए सभी समितियों के डेटाबेस को अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

जिलेवार, पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए। ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, उन्हें लक्ष्य में रखकर नवीन समितियों का गठन किया जाए।

इसी प्रकार उन्होंने विश्व अन्न भंडारण योजना, भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-डिस्ट्रिक्स सर्विस की स्थिति सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की गई। यथा संभव समस्त सहकारी संस्थाओं के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अनिवार्यता खोले जाना चाहिए, जिससे सहकारिता का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

बाबू भैया की कलम से ✍

राज्यपाल की समीक्षा बैठक के मायने क्या ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका खुद ही जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक जिलों में जाकर ले रहे हैं। प्रदेश के जिलों के प्रत्येक विभागों के क्रियाकलापों को समझने का स्वयं प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर से इसकी शुरुवात देखने में आई। ये बैठकें जिलों में जाकर वे क्यों ले रहे हैं ? क्या चाहते हैं ? ये तो उन्हें ही पता होगा। जनमानस को लगा है कि शायद यह प्रक्रिया सभी राज्यों के राज्यपालों को अपनाने की सलाह केंद्र ने दी होगी या राज्यपाल यह स्वयं अपनी मर्जी से कर रहें हैं। अथवा छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार से उनको कोई नाराजी हो गई है। हम यहां ये नहीं कहना चाहते कि राज्यपाल को अधिकारियों से बातचीत के अधिकार नहीं है। सरकार उनके नाम पर चलती है ,यह भी सब जानते हैं। अब तक देखा जा रहा था कि सभी राज्यपाल एक परम्परा से बंधे रहते हैं। राज्यपाल को वैसे तो सीमित अधिकार होते हैं,जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। उसके बावजूद समय समय पर देखा जा रहा है कि राज्यपाल अपनी परम्परागत सीमाओं से बाहर जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल जैसे अनेक प्रदेशों के राज्यपालों ने इसके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। जिस पर जन मानस सोचने को मजबूर भी हुआ है। जब जब राज्यपालों ने सीमाओं के बाहर राजनीतिक बयानबाजी की है,तब तब देश में इसकी चर्चा व्यापक रूप से हुई है। जनमानस दो विचारों के द्वंद में फंस गया है। एक विचार राज्यपालों के परम्परा से हट कर राज्यों में हस्तक्षेप करने को उचित मानने वालों का है। दूसरा इसे संविधान में किये उल्लेख का उल्लंघन मान रहा है। संविधान के अनुच्छेद 167 (क) में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित किये जाएं।167 (ख) में साफ उल्लेख है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगें वह दे और (ग)में कहा गया है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय किया हो ,किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है,राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यह साफ उल्लेख है उसके बाद कौन सी ऐसी बात राज्यपाल जानना चाहते थे कि उन्हें जिलों में जाकर जानने की जरूरत पड़ रही है। यह प्रश्न विष्णुदेव सरकार के समक्ष पैदा हो सकता है। कौन सही है कौन गलत जनमानस इस बात पर असमंजस में दिखाई देता है। सब देखते आ रहे हैं कि राज्यपाल जब भी कोई बात समझना चाहे या किसी संज्ञान में आये मामले में कुछ कहना चाहे,निर्देश देना चाहे तो राजभवन से पत्र व्यवहार करते हैं। अथवा सम्बंधित अधिकारी को तलब कर बात कर लेते हैं,अथवा मुख्य सचिव या मंत्रीगण को बुलाकर बात करके समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री जब जब उनसे मिलते हैं तब सारी शंकाओं का समाधान भी किया जा सकता है। जिलों में जाकर विभागीय अधिकारियों से बातचीत सिर्फ औपचारिकता नहीं हो सकती। इसकी चर्चा जनमानस में है कि कहीं वर्तमान सरकार के कामकाज से राज्यपाल नाखुश तो नहीं हैं। राज्यपाल रमन डेका अभी हाल छत्तीसगढ़ आये हैं। भेंट मुलाकात ,जान पहचान करना अलग बात है। समीक्षा बैठकें लेकर हालात जानना अलग बात है। अभी तक विभागीय मंत्रीगण,मुख्यमंत्री के साथ विभागीय प्रमुख सचिव,सचिव ,जिलों के प्रभारी सचिवों तथा मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है कि वे जिलों तक पहुंचें व विभागीय समीक्षा कर सम्बन्धितों को रिपोर्ट करे। वो रिपोर्ट क्रम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल तक को पहुंचे ताकि प्रशासन सुचारू ढंग से चले। क्षेत्रों की जरूरतों की समझ बने,आंतरिक हालात से सरकार रूबरू हो। सुधार के निर्देश दिए जाएं या अच्छा काम हो रहा है तो पीठ थपथपाई जा सके। जब जरूरत हो तो प्रदेश की सारी प्रशासनिक स्थिति से केंद्रीय आलाकमान को भी अवगत कराया जा सके। जनमानस में एक और चर्चा चल पड़ी है कि अगर राज्यपाल स्वयं ही समीक्षा बैठकें लेकर जानकारी प्राप्त करने लगेंगें तो मन्त्रीगण व अधिकारी गण क्या करेंगें ? किसको रिपोर्ट करेंगें। इस बात पर कोई रोक नहीं है कि राज्यपाल जिलों में जाकर किसी से मिलें, लेकिन अगर अधिकारियों से राज्यपालों की समीक्षा बैठकें होने लगें तो क्यों ना मान लेना चाहिए कि कहीं केंद्र से राज्यपालों को राज्यों पर नकेल कसने के कोई विशेष निर्देश तो नही हैं, या प्रदेशों के प्रशासनिक तरीकों में कोई बड़ा बदलाव तो होने नहीं जा रहा है। राज्यपाल स्वयं प्रदेश का दौरा कर प्रशासनिक स्थिति पर नजर रखने की कोई नई प्रक्रिया तो अपनाने नहीं जा रहे हैं। सविधान में उनको ऐसा करने से मना करने के किसी प्रकार के प्रावधान नहीं हैं कि वे समीक्षा बैठकें नहीं कर सकते। लेकिन अनुच्छेद 167 में कुछ निर्देश हैं जिससे यह समझ में आता है कि वे जब चाहें किसी प्राधिकारी को बुलाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके ये राज्य के प्राधिकारी जानकारी देने बाध्य हैं। जनता में चर्चा है कि फिर जिलों में जाकर बैठकों की जरूरत क्यों पड़ी है यह विचारणीय बात है।

छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार से होगी सम्मानित

मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पी श्रीमती हीराबाई को प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। श्रीमती बघेल ढोकरा बेलमेटल शिल्प की प्रसिद्ध शिल्पकार है। अधिसूचना के अनुसार पांच शिल्प गुरू तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव ने शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है।

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के वनांचल ग्राम पंचायत बैगीनडीह की ढोकरा बेलमेटल शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल इसके पूर्व भी अपनी कलाकारी का डंका बजा चुकी है।

श्रीमती बघेल को बेलमेटल शिल्प कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2011-12 में पुरुस्कृत किया गया जा चुका है। उनके पति श्री मिनकेतन बघेल को भी वर्ष 2006-07 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के लिए चयनित शिल्पी श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल ने कहा कि मेरे पिता श्री भुलाऊ झरेका व पति ही मेरी प्रेरणास्रोत है, जिन्होंने मुझे ढोकरा बेलमेटल कला सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।

बी.एड., डी.एल.एड., बी.ए.बी.एड. एवं बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2024 की घोषणा

पंजीयन एवं ऑनलाईन विकल्प फार्म 05 से 11 सितम्बर तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय और निजी शिक्षा महाविद्यालयों में द्विवर्षीय बी.एड., डी.एल.एड., चार वर्षीय बी.ए.बी.एड., और बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जो प्री.बी.एड., प्री.डी.एल.एड., या प्री टेस्ट 2024 में सम्मिलित हुए हैं, वे 5 सितंबर 2024 से 11 सितंबर 2024 तक चिप्स के आधिकारिक वेबसाइट https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/ पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए एससीईआरटी रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://scert.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देशों और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी। अभ्यर्थी अपनी दावा आपत्ति और पत्र व्यवहार ईमेल के माध्यम से E-mail suport.slcm@cgchips.in पर भेज सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर 7470470609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह

प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर 3 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार

52 राज्यपाल शिक्षक सम्मान से होंगे सम्मानित

रायपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 05 सितंबर 2024 को प्रात: 11 बजे से राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 55 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 52 शिक्षक राज्यपाल शिक्षक सम्मान और 3 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार वर्ष 2024

शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के तीन महान साहित्यिक विभूतियों के नाम पर तीन शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। इनमें बिलासपुर जिले की व्याखाता डॉ. रश्मि सिंह धुर्वे को ''डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार'', कबीरधाम जिले के शिक्षक री राजर्षि पाण्डेय को ''डॉ. मुकुटधर पाण्डेय स्मृति पुरस्कार'', दुर्ग जिले की उच्च वर्ग शिक्षक डॉ. श्रीमती सरिता साहू को ''डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार'' प्रदान किया जाएगा।

राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023-24

राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023-24 से सम्मानित होने वाले 52 शिक्षकों में दंतेवाड़ा जिले की व्याख्याता श्रीमती नेहा नाथ और शिक्षक एलबी कुमारी माधुरी उके, सरगुजा जिले की प्रधान पाठक कुमारी मधु सोनवानी और व्याख्याता श्रीमती नीतु सिंह यादव, सूरजपुर जिले की व्याख्याता एलबी श्रीमती रीता गिरी और प्रधान पाठक कुमारी विनिता सिंह, बालोद जिले के व्याख्याता एलबी श्री धर्मेन्द्र कुमार और व्याख्याता डॉ. भरतलाल साहसी, जशपुर जिले के व्याख्याता एलबी श्री टुमनु गोसाई और श्री अयोध किशोर गुप्ता, सुकमा जिले की प्रधान पाठक श्रीमती जयमाला और श्री हपका मुत्ता, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के सहायक शिक्षक श्री नीलकंठ कोमरे और अंगद सलामें, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सहायक शिक्षक श्रीमती स्वप्निल सिंह पवार और शिक्षक एलबी अर्चना सामुएल मसीह, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के व्याख्याता एलबी श्री मानस साहू और सहायक शिक्षक एलबी श्री महादीप जंघेल, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के व्याख्याता श्री सेवक राम निषाद और व्याख्याता एलबी श्री पवन कुमार सेन, कोण्डागांव जिले की व्याख्याता श्रीमती तनुजा देवांगन और उच्च श्रेणी शिक्षक श्रीमती सरस्वती नाग, कोरिया जिले की सहायक शिक्षक एलबी श्रीमती श्वेता सोनी और श्रीमती अर्पणा मिश्रा, राजनांदगांव जिले के व्याख्याता एलबी श्री गोकुल दास जंघेल और श्री जयप्रकाश साहू के नामों की विधिवत् घोषणा की। राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए चयनित शिक्षकों में नारायणपुर जिले की शिक्षक एलबी श्रीमती कविता हिरवानी और व्याख्याता एलबी श्रीमती लता मानिकपुरी, जांजगीर-चांपा जिले के व्याख्याता एलबी श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी और सहायक शिक्षक एलबी श्री कामता प्रसाद सिंह, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सहायक शिक्षक एलबी सुनिता यादव और व्याख्याता श्री पूनम सिंह साहू, बेमेतरा जिले की सहायक शिक्षक एलबी सुश्री हिमकल्याणी और व्याख्याता एलबी श्री भुवनलाल साहू, महासमुंद जिले के व्याख्याता श्री प्रमोद कुमार कन्नौजे और व्याख्याता एलबी श्री शैलेन्द्र कुमार नायक, बलरामपुर जिले के शिक्षक श्री श्याम कुमार गुप्ता और प्रधान पाठक श्री विनोद कुमार पंथ, मुंगेली जिले के शिक्षक एलबी डॉ. श्री सत्यनारायण तिवारी और प्रधान पाठक श्री जितेन्द्र गेंदले, गरियाबंद जिले के सहायक शिक्षक एलबी श्री डिगेश्वर कुमार साहू और उच्च श्रेणी शिक्षक श्री किशोर कुमार निर्मलकर, धमतरी जिले की व्याख्याता एलबी श्रीमती ज्योति मगर और डॉ. आशीष नायक, रायगढ़ जिले की प्रधान पाठक डॉ. मनीषा त्रिपाठी और सुशील कुमार गुप्ता, कोरबा जिले के व्याख्याता श्री भुपेन्द्र कुमार राठौर और सहायक शिक्षक श्रीमती वसुंधरा कुर्रे, जगदलपुर जिले की व्याख्याता श्रीमती मीरा हिरवानी और मोहम्मद अकबर खान, बीजापुर जिले के प्रधान पाठक श्री पवन कुमार सिन्हा और शिक्षक एलबी श्री ककेम नारायण के नाम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने गुरूजनों को शिक्षक दिवस पर दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारतरत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉ. राधाकृष्णन दार्शनिक और शिक्षक भी रहे हैं। देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक, शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। वे उच्च नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों के जीवन में उतारकर अच्छा नागरिक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा है कि डॉ. राधाकृष्णन के पदचिन्हों पर चलते हुए देश और समाज को सकारात्मक दिशा देने में आगे भी शिक्षकगण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सिंहदेव को बनाए गए मेनिफेस्टो कोआर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी

रायपुर. एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें मेनिफेस्टो कोआर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी बनाए गए हैं. सिंहदेव को 4 राज्यों हरियाणा, जम्मू काश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के मेनिफेस्टो समिति की जिम्मेदारी दी गई है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाने में टीएस सिंहदेव ने बड़ी भूमिका थी. इन्ही घोषणा पत्र के बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आई थी.

उप मुख्यमंत्री साव 5 सितम्बर को विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल

रायपुर. उप मुख्यमंत्री अरुण साव 5 सितम्बर को मुंगेली जिले के लोरमी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे 5 सितम्बर को सवेरे दस बजे बिलासपुर से सड़क मार्ग से लोरमी के लिए रवाना होंगे। वे सवेरे 11 लोरमी के चारखम्भा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री साव दोपहर 12 बजे लोरमी के कबीर भवन में नगर पालिका द्वारा किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.